Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-19, अंक-15 01-15 अगस्त, 2024 (पाक्षिक) ₹20

देश की रक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदीजी ने किया है

केन्द्रीय बजट 2024-25

बजट की प्राथमिकताएं

कृषि में उत्पादकता और अनुकूलन

रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

विनिर्माण और सेवाएं

शहरी विकास

ऊर्जा सुरक्षा

अवसंरचना

नवाचार, अनुसंधान और विकास

अगली पीढ़ी के सुधार

‘यह बजट विकसित भारत के लिए है’

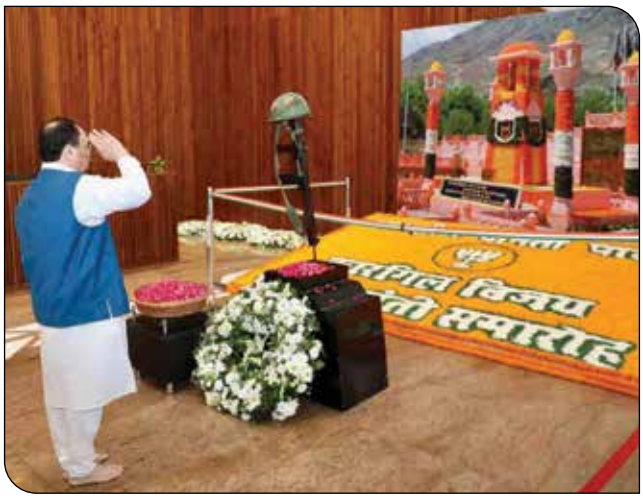

भाजपा मुख्यालय विस्तार (नई दिल्ली) में 26 जुलाई, 2024 को कारगिल विजय दिवस रजत जयंती कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 25 जुलाई, 2024 को कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित 'मशाल रैली' में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

पुरी (ओडिशा) में 19 जुलाई, 2024 को आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में दीप प्रज्वलित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

लखनऊ में 14 जुलाई, 2024 को आयोजित प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेतागण

पुणे (महाराष्ट्र) में 21 जुलाई, 2024 को भाजपा प्रदेश अधिवेशन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेतागण

रांची (झारखंड) में 20 जुलाई, 2024 को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 यह बजट 'गांव, गरीब और किसानों' के लिए है: प्रधानमंत्री मोदी

नीतिगत अनिश्चितताओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बावजूद भारत का आर्थिक विकास एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है और आने वाले वर्षों में भारत इसी प्रकार प्रगति की राह पर...

15 केंद्रीय बजट 2024-25 समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 समाज के हर वर्ग को शक्ति...

24 प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर लद्दाख का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 जुलाई को 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान...

25 देश की रक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदीजी ने किया है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 जुलाई, 2024 को...

26 'अगर पाकिस्तान उकसाने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा 25 जुलाई, 2024 को...

वैचारिकी

भारतीय जनसंघ ही क्यों? / **डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी** 28

लेख

ताकि सबको मिले पूरा पोषक भोजन / **जगत प्रकाश नड्डा** 32

श्रद्धांजलि

नहीं रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं 'कमल संदेश' के पूर्व संपादक प्रभात झा 30

अन्य

केंद्रीय बजट 2024-25: एक नजर में 14

आर्थिक समीक्षा 2023-24: प्रमुख बातें 18

भाजपा की सफलता में प्रत्येक कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण योगदान होता है : अमित शाह 27

350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी का 'वाघ नख' भारत वापस आया 33

देश में रोजगार 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान और देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं।

(26 जुलाई, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा

लगातार तीनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कुल मिलाकर जितने सांसद जीतकर आए हैं, वह मिलाकर भी इस चुनाव में भाजपा के विजयी सांसद से कम हैं। 'इंडी गठबंधन' के सारे सांसद मिलकर भी अकेले भाजपा के सांसदों से कम हैं।

आश्चर्य! फिर भी कांग्रेस उल्लास मना रही है!

(14 जुलाई, 2024)

अमित शाह

जीतकर अहंकारी होने के दुनिया में बहुत उदाहरण हैं, मगर राहुल गांधी लगातार हारकर भी अहंकारी होने का अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं।

(21 जुलाई, 2024)

राजनाथ सिंह

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुईं और जिस तरह का दमनकारी चक्र चलाया गया, वह आज भी देशवासियों की स्मृति में ताज़ा है। भारत में आपातकाल थोपकर संविधान का गला घोंटने का जो प्रयास किया गया, उसको याद दिलाने के लिए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनेवाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 25 जून को #SamvidhaanHatyaDiwas घोषित किया है। आपातकाल में जिन्होंने भी जेल काटी और यातनाएं सहीं, उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। (12 जुलाई, 2024)

बी.एल. संतोष

मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई। दोनों ने शानदार कौशल और टीम वर्क दिखाया है। मनु भाकर को उनके दूसरे कांस्य पदक के लिए दोहरी बधाई। #Cheer4Bharat

(30 जुलाई, 2024)

निर्मला सीतारमण

इस बजट के जरिए बैंक एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के लोन देंगे। साथ ही, एमएसएमई ने शिकायत की है कि बैंक उनके टर्नओवर चक्र या व्यवसाय को नहीं समझते हैं और इसलिए उन्हें लोन देने में संकोच करते हैं। बैंक अब इस पर काम करेंगे और हमने सिडबी द्वारा प्रमुख एमएसएमई क्लस्टर में अपनी नई शाखाएं खोलने का भी प्रावधान किया है। (28 जुलाई, 2024)

संपादकीय

'विकसित भारत' के सपनों को साकार करता केन्द्रीय बजट 2024-25

केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2024-25 का बजट 'विकसित भारत के उन स्वप्नों को साकार करेगा, जिससे देश के सर्वांगीण, समावेशी एवं संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में इस बजट के विभिन्न प्रावधानों में जन-जन का सुदृढ़ विश्वास प्रतिबिंबित हो रहा है। इससे देश के स्वप्नों एवं आकांक्षाओं को नए पंख लगे हैं। इसमें भारत के 'अमृतकाल' में गरीब, अन्नदाता, युवा एवं नारी समेत समाज के सभी वर्गों के सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। कैपेक्स को 11,11,111 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत) करने से विशेषकर ग्रामीण भारत की अवसंरचना मजबूत होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी।

जनजातीय परिवारों के लिए 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के संतृप्तीकरण, आकांक्षी जिलों का विकास और गरीबों के अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य इस बजट में है। अमृतपीढ़ी के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बजट में युवाओं के लिए रोजगार, उनका कौशल विकास, एमएसएमई की मजबूती के साथ इस बजट में 20 लाख युवाओं को आने वाले पांच वर्षों में प्रशिक्षित करने की योजना है। पिछले दस वर्षों में किसानों को राष्ट्र के विकास के केन्द्र में रखने के जो निरंतर प्रयास हुए हैं तथा अनेक अभिनव योजनाओं के साथ उन्हें लागत का डेढ़-गुणा अधिक एमएसपी दिया जा रहा है, उसी दिशा में बजट में अनेक नई पहलें की गई हैं, जिससे कृषि का भविष्य उज्ज्वल होगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा तथा अनुसंधान एवं डिजिटल तकनीक से कृषि क्षेत्र का विकास होगा।

महिलानीत विकास की अवधारणा के अनुरूप बजट में महिला सशक्तीकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का प्रावधान किया गया है। मध्यम वर्ग एवं करदाताओं को सशक्त बनाने के लिए बजट उन्हें केंद्र में रखते हुए करों तथा टीडीएस एवं संबंधी व्यवस्था का सरलीकरण किया है। 'मिशन पूर्वोदय' के जरिए उत्तर-पूर्व के राज्यों में शांति की स्थापना कर विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है तथा उसमें अब पूर्व के झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को भी शामिल किया गया है। अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को गया में औद्योगिक नोड खोलकर विकसित किया जाएगा। इससे भविष्य में प्राचीन केंद्र, सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ आधुनिक अर्थव्यवस्था के केन्द्र भी बनेंगे। यह 'विकास भी, विरासत भी' के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है।

अर्थव्यवस्था में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित कर निवेश, कैपेक्स तथा जनसेवा के कार्य से व्यापक परिवर्तन लाने में एनडीए सरकार को भारी सफलता मिली है। यह एनडीए सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि जब विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति एवं गिरती विकास दर के दबाव में हैं, भारत आज एक चमकता सितारा है

ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेसनीत यूपीए के दौर के कुशासन, भ्रष्टाचार, लूट एवं पॉलिसी पैरालिसिस के फलस्वरूप निराशापूर्ण वातावरण में एक डूबती अर्थव्यवस्था एनडीए सरकार को 2014 में विरासत में मिली थी। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित कर निवेश, कैपेक्स तथा जनसेवा के कार्य से व्यापक परिवर्तन लाने में एनडीए सरकार को भारी सफलता मिली है। यह एनडीए सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि जब विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति एवं गिरती विकास दर के दबाव में हैं, भारत आज एक चमकता सितारा है। भारत की विकास दर निरंतर 6.5-7 प्रतिशत रही है और वित्तीय घाटा निरंतर कम हो रहा है। आज महंगाई नियंत्रण में है और मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वे अपने तीसरे कार्यकाल में तीन गुणा अधिक कार्य करेंगे, श्रीमती निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था पर तीन गुणा अधिक प्रभाव वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई की पात्र हैं। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

यह बजट 'गांव, गरीब और किसानों' के लिए है: प्रधानमंत्री मोदी

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में 'केन्द्रीय बजट 2024-25' प्रस्तुत किया। 'विकसित भारत' के लिए सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित करने वाला यह बजट न केवल करोड़ों नए रोजगार के अवसरों का सृजनकारी है, बल्कि शिक्षा व कौशल को नया आयाम देने वाला है। केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये; पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए; कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा मुद्रा ऋणों की सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए तक किया गया है। बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर काफी जोर दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये तथा उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये है। बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जिससे देश का स्थायी विकास सुनिश्चित होगा। वास्तव में जनहितैषी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में काफी सहायक सिद्ध होगा

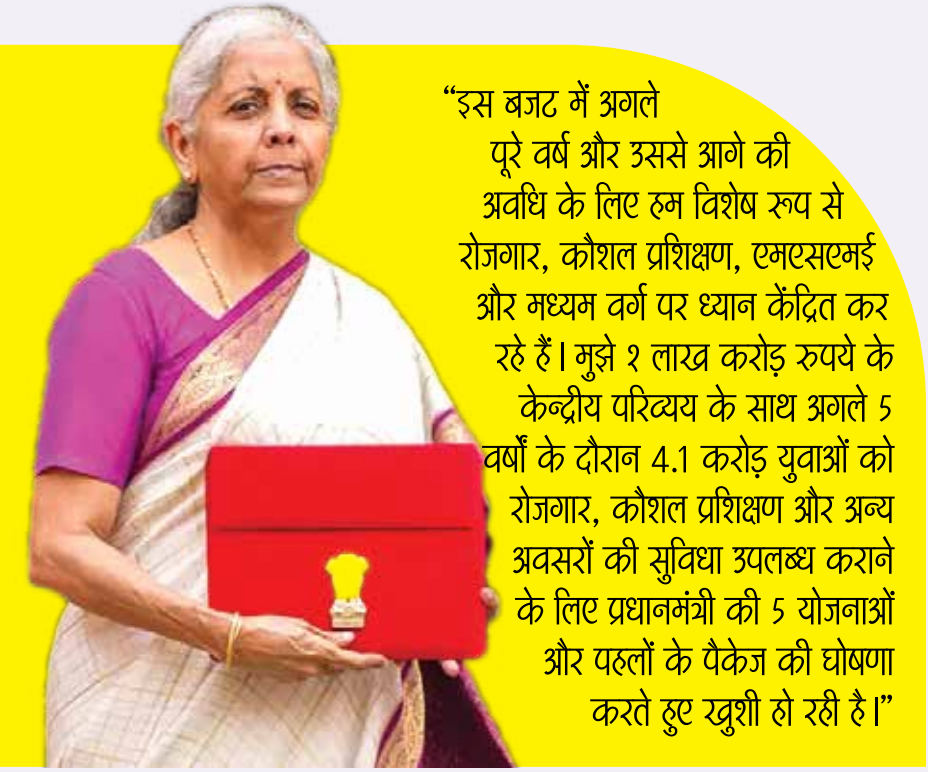

"इस बजट में अगले पूरे वर्ष और उससे आगे की अवधि के लिए हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे 1 लाख करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों के दौरान 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।"

नीतिगत अनिश्चितताओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बावजूद भारत का आर्थिक विकास एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है और आने वाले वर्षों में भारत इसी प्रकार प्रगति की राह पर अग्रसर रहेगा। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को संसद में 'केन्द्रीय बजट 2024-25' पेश करते हुए कहा कि भारत की मुद्रास्फीति की दर कम है और यह स्थिर बनी हुई है। मुद्रास्फीति की दर 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। वर्तमान में प्रमुख मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-इंधन) 3.1 प्रतिशत है तथा जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की बाजार में पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।

अंतरिम बजट

वित्त मंत्री ने कहा कि जैसा अंतरिम बजट में कहा गया था, हमें 4 मुख्य समुदायों— 'गरीब', 'महिला', 'युवा' और 'अन्नदाता' पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

बजट की मुख्य विषयवस्तु

बजट की विषयवस्तु के बारे में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस बजट में अगले पूरे वर्ष और उससे आगे की अवधि के लिए हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों के दौरान 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा की। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्राथमिकता 1 : कृषि में उत्पादकता और अनुकूलन

वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।

अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी।

बजट प्राथमिकताएं

वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के सृजन हेतु निम्न 9 प्राथमिकताओं के संबंध में स्थायी प्रयासों की परिकल्पना की गई है:

- कृषि में उत्पादकता और अनुकूलन
- रोजगार और कौशल प्रशिक्षण
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण और सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- अवसंरचना
- नवाचार, अनुसंधान और विकास
- अगली पीढ़ी के सुधार

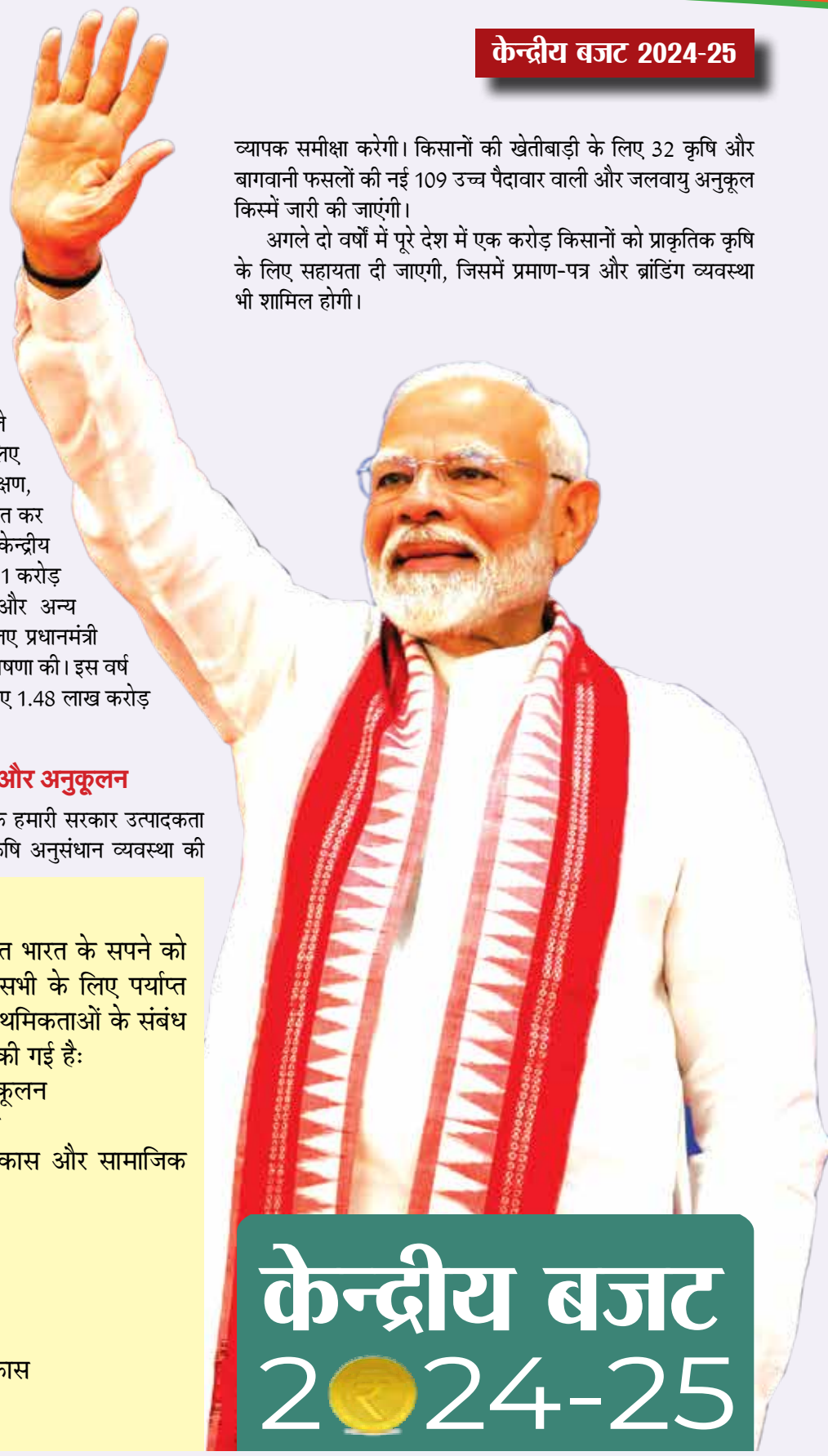

10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाएगी ताकि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए 'आत्मनिर्भरता' हासिल की जा सके।

3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को कवर करने के उद्देश्य से सरकार राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करेगी।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष के लिए कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की।

प्राथमिकता 2 : रोजगार और कौशल

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री की योजना के एक अंग के तौर पर रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन और पहली बार रोजगार प्राप्त कर्मचारियों की पहचान पर ध्यान और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं की सहायता पर आधारित होंगी।

सरकार उद्योग और क्रेचों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों के गठन के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं की अधिक भागेदारी की भी सुविधा प्रदान करेगी।

कौशल से जुड़े कार्यक्रमों का संदर्भ देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकारों और उद्योगों के सहयोग से कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत चौथी योजना के तौर पर एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाया जाएगा

और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का एक ही केंद्र में उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ-साथ इनके परिणामों के आधार पर अन्य व्यवस्थाओं में भी वृद्धि की जाएगी।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार से प्रोत्साहित कोष के माध्यम से 7.5 लाख रुपये तक की गारंटी के साथ ऋण की सुविधा के साथ मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन किया जाएगा और इससे प्रति वर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत किसी भी लाभ के पात्र नहीं होने वाले युवाओं की सहायता के लिए घरेलू

संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।

प्राथमिकता 3 : समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

संतृप्तता दृष्टिकोण पर अपने विचार रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से शिल्पियों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों एवं रेहड़ी पटरी वालों के लिए आर्थिक गतिविधियों में सहायता देने वाली इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर देने के साथ-साथ इनमें और गति लाई जाएगी।

पूर्वोदय

सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी हिस्से के समग्र विकास के लिए एक पूर्वोदय योजना तैयार करेगी। इसमें विकसित भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचा और आर्थिक अवसर का सृजन शामिल होगा।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय परिवारों और 63 हजार गांवों को शामिल करने वाले आकांक्षीय जिलों एवं 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ देने के लिए समग्र विकास के दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ करेगी।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं में विस्तार करते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज्यादा शाखाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र में गठन किया जाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वर्ष ग्रामीण बुनियादी ढांचे के साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्राथमिकता 4 : विनिर्माण और सेवाएं

एमएसएमई के संवर्धन के लिए सहायता

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार के बजट में विशेष रूप से श्रम प्रोत्साहन विनिर्माण के साथ-साथ एमएसएमई और विनिर्माण पर खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपये तक के गारंटी कवर के साथ प्रत्येक आवेदक को एक पृथक रूप से तैयार स्वयं-वित्तीय गारंटी कोष प्रदान किया जाएगा, जबकि इसमें ऋण धनराशि और अधिक हो सकती है। इसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय ऋण के लिए एमएसएमई का मूल्यांकन करने के लिए अपनी अंदरूनी क्षमता को विकसित करेंगे।

उन्होंने एमएसएमई के लिए बैंक ऋण में निरंतरता बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नए तंत्र की भी घोषणा की।

मुद्रा ऋण

मुद्रा ऋणों की सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए तक किया जाएगा और यह सुविधा उन उद्यमियों के लिए होगी,

जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत अपने पुराने ऋणों का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है।

फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां

एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रस्थापित किए जाएंगे।

शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप

प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में हमारी सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत करेगी।

प्राथमिकता 5 : शहरी विकास

शहरी आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

राज्य सरकारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी में हम भरोसेमंद परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे।

पीएम स्वनिधि

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के जीवन में बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण पीएम स्वनिधि योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाटों' और स्ट्रीट फूड केंद्रों के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की है।

प्राथमिकता 6 : ऊर्जा सुरक्षा

अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना पर लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है, जिसके अंतर्गत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा हम इसे आगे और प्रोत्साहित करेंगे।

'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में ऊर्जा जरूरतों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में परमाणु ऊर्जा के तैयार होने की आशा है।

प्राथमिकता 7 : अवसंरचना

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में अवसंरचना का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश

का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की आवश्यकताओं के अनुरूप अगले 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष मैंने पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

वित्त मंत्री ने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई के लिए पात्र बने 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पीएमजीएसवाई का चरण IV आरंभ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बिहार ने अक्सर बाढ़ को झेला है, उनमें से बहुतों की उत्पत्ति देश से बाहर होती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजनाओं पर प्रगति होनी बाकी है। हमारी सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के माध्यम से 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और बैराजों, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

इसके अलावा, सरकार बाढ़ प्रबंधन, भू-स्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को भी सहायता प्रदान करेगी।

प्राथमिकता 8 : नवाचार, अनुसंधान और विकास

वित्त मंत्री ने कहा कि हम मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा, हम अंतरिम बजट में घोषणा के अनुरूप 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल से वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था स्थापित करेंगे।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुणा बढ़ाने पर निरन्तर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था जाएगी।

प्राथमिकता 9 : अगली पीढ़ी के सुधार

आर्थिक नीति फ्रेमवर्क

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने हेतु एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाएंगी और रोजगार के अवसरों तथा सतत उच्च विकास के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय करेगी।

श्रम संबंधी सुधार

हमारी सरकार श्रमिकों के लिए कई सेवाओं के प्रावधान की सुविधा देगी, सरकार श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं के प्रावधान को सुगम बनाएगी, जिनमें रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं शामिल होंगी। ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से ऐसा वन-स्टॉप समाधान सुगम होगा। उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की सुगमता बढ़ाने हेतु श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत किया जाएगा।

सरकार जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिए एक टैक्सोनॉमी विकसित करेगी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल किया जाएगा ताकि (1) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सुविधा हो (2) प्राथमिकताओं पर आधारित निवेश हो सके और (3) ओवरसीज निवेशों के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये के उपयोग के लिए अवसरों को बढ़ावा मिले।

एनपीएस वात्सल्य

माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस-वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। वयस्कता की आयु होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

नई पेंशन योजना (एनपीएस)

वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है और एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा, जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता बनाए रखी जाएगी।

बजट अनुमान 2024-25

वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमशः 32.07 लाख करोड़ रुपये और 48.21 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं। निवल कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः 14.01 लाख करोड़ रुपये और 11.63 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि मेरे द्वारा 2021 में घोषित राजकोषीय समेकन उपाय से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ है और हमारा लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है।

चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनधारकों को राहत

प्रत्यक्ष करों में देश के चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनधारकों को राहत प्रदान करने के अतिरिक्त केन्द्रीय बजट 2024-25 में अगले छह महीनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की व्यापक रूप से समीक्षा करने, उन्हें सरल बनाने, टैक्स लगाए जाने और अनुपालन बोझों में कमी करने तथा कर के दायरे को विस्तारित करने की बात की गई है। टैक्स आधार में सुधार लाने और घरेलू विनिर्माण में सहायता करने के लिए सीमा शुल्क दर संरचना की समीक्षा के साथ-साथ बजट में जीएसटी कर संरचना के व्यापक युक्तीकरण की बात की गई है।

आयकर अधिनियम की एक व्यापक समीक्षा का लक्ष्य विवादों और मुकदमों में कमी लाना तथा अधिनियम को सरल संक्षिप्त तथा पढ़ने में सरल बनाना है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि कॉरपोरेट तथा व्यक्तिगत आयकर के लिए छूटों एवं कटौतियों के बिना कर व्यवस्था के सरलीकरण की करदाताओं द्वारा सराहना की गई है, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स में 58 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 2022-23 में सरलीकृत कर व्यवस्था से आया और दो-तिहाई से अधिक करदाता नए व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था से जुड़ चुके हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया

बजट 2024-25 में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार पेंशन धारकों के लिए फैमली पेंशन पर डिडक्शन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। अब आकलनों को फिर से खुलने की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है, अगर छुपाई गई आय 50 लाख रुपये से अधिक है। नई कर व्यवस्था दर संरचना में भी संशोधन किया गया है जिससे कि वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक का लाभ प्राप्त हो सके।

नई कर व्यवस्था दर संरचना

आयकर स्लैब	कर दर
0-3 लाख रुपये	शून्य
3-7 लाख रुपये	5 प्रतिशत
7-10 लाख रुपये	10 प्रतिशत
10-12 लाख रुपये	15 प्रतिशत
12-15 लाख रुपये	20 प्रतिशत
15 लाख रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

समाप्त हुआ एंजल टैक्स

निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार में तेजी लाने के लिए बजट ने उद्यमशील भावना तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया है, सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त, देश में घरेलू क्रूज का संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए एक सरल कर व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया

है। देश में अपरिष्कृत हीरा बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियां के लिए सेफ हार्बर दरों से अब लाभ उठा सकती हैं, जिससे हीरा उद्योग को लाभ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त, विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरल हुई प्रत्यक्ष कर व्यवस्था

बजट में धर्मार्थ संस्थाओं, टीडीएस दर और कैपिटल गेन कराधान के लिए प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। धर्मार्थ कार्यों के लिए कर में छूट की दो व्यवस्थाओं को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव है। अनेक भुगतानों पर 5 प्रतिशत टीडीएस दर को घटाकर 2 प्रतिशत टीडीएस दर किया जा रहा है और म्युचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद से भुगतानों में 20 प्रतिशत टीडीएस दर को समाप्त किया जा रहा है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से कम करके 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

साथ ही, टीसीएस की राशि को वेतन पर कटौती किए जाने वाले टीडीएस की गणना में लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, टीडीएस के भुगतान में विलम्ब को टीडीएस के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक गैर-अपराधीकरण (डिक्रिमिनलाइज) किए जाने का प्रस्ताव है। टीडीएस बकायों के लिए एक मानक कार्यप्रणाली प्रक्रिया (एसओपी) लाने और ऐसे बकायों के लिए कम्पाउंडिग दिशा-निर्देशों को सरल तथा युक्तिसंगत बनाने की भी योजना बनाई जा रही है।

अब से कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5 प्रतिशत का कर दर लगेगा। बजट में निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के लाभ के लिए कैपिटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है।

एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि गैर-सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए इन्हें कम से कम दो वर्षों के लिए होल्ड करना होगा।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि गैर-सूचीबद्ध बांड और डिबेंचर्स, डेब्ट म्युचुअल फंडों और मार्केट लिंक्ड डिबेंचरों पर होल्डिंग पीरियड चाहे जो भी हो, कैपिटल गेन टैक्स लागू कर दर से देय होगा।

यह स्वीकार करते हुए कि जीएसटी ने आम आदमी पर कर के बोझ को कम किया है और इसे अपार सफलता करार देते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी ने अनुपालन के बोझ तथा व्यापार एवं उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम किया है। बजट में सीमा शुल्क तथा आयकर की शेष सेवाओं को और डिजिटलाइज तथा कागज रहित बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें सुधार और अगले दो वर्षों में अपीली ऑर्डर को प्रभावी बनाने के आदेश शामिल हैं।

सीमा शुल्क युक्तिसंगत बनाया गया

सीमा शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए संशोधित किया गया है और व्यापार की सुगमता तथा विवादों में कमी लाने के लिए संशोधन किया गया है। कैंसर रोगियों को राहत देते हुए बजट में कैंसर की उपचार वाली तीन और दवाइयों, जिनके नाम हैं— ट्रस्टूजुमैब डेरूक्सटीकैन, ओसीमर्टीनीब तथा दुर्वालुमैब को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दे दी गई है। चिकित्सीय एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक्स-रे ट्यूबों और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कमी लाई जाएगी।

मोबाइल फोन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग तथा रिफाइनिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में लीथियम जैसे 25 दुर्लभ पृथ्वी खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी गई है उनमें से 2 पर बीसीडी घटा दिया गया है।

बजट में सोलर पैनलों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं को छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। भारत के सीफूड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रूडस्टॉक, पॉलीस्ट वॉर्म, श्रिम्प तथा फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। बजट से भारतीय चमड़ा और निर्यात की वस्त्र उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। स्पेंडेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त मिथलिन डिफनिल डाइसोकाइनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6 प्रतिशत हुआ

सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत और प्लेटिनम पर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है। फेरो निकल तथा ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटा दिया गया है, जबकि पाइपलाइन में विद्यमान तथा नई क्षमताओं की सहायता करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट पर बीसीडी 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार पर्यावरण के लिए नुकसानदायक समझते हुए पीवीसी फ्लैक्स बैनर्स पर बीसीडी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट दूर संचार उपकरणों के पीसीबीए पर बीसीडी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

विवादों के समाधान तथा बैकलॉग के निपटान के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपील में लंबित कुछ खास आयकर विवादों के निवारण के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का प्रस्ताव रखा। उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय तथा ट्रिब्यूनलों में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर तथा सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, मुकदमेबाजी में कमी लाने तथा अंतरराष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के लिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे को बढ़ाया जाएगा तथा ट्रांसफर प्राइसिंग आकलन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। ■

केंद्रीय बजट 2024-25: एक नजर में

- दो लाख करोड़ रुपये की लागत से पांच योजनाओं और पहलों से संबंधित प्रधानमंत्री का पैकेज अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा देगा
- 'विकसित भारत' को साकार करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के सृजन हेतु 9 प्राथमिकताओं के लिए सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है
- बजट 2024-25 का रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष जोर
- किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 बागवानी फसलों की उच्च-उपज वाली तथा जलवायु-अनुकूल 109 नई किस्में जारी की जाएंगी
- अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि की शुरुआत करने के लिए सहायता दी जाएगी
- इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा
- सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना को अंतिम रूप देगी जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं
- महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है, जिनसे महिलाओं और लड़कियों को लाभ होगा
- इस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना समेत ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- मुद्रा ऋण की सीमा को वर्तमान के 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा
- भारत की मुद्रास्फीति दर निचले स्तर पर बनी हुई है और स्थिर है, यह 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है
- सरकार अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना का शुभारंभ करेगी
- पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों की आवास आवश्यकताओं का समाधान किया जाएगा, इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा
- 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के उपयुक्त सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई के चरण-IV की शुरुआत की जाएगी

- 1,000 करोड़ रुपये की वेंचर कैपिटल निधि के साथ अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 5 गुना विस्तार करने पर जोर
- 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आयकर में बड़ी राहत
- नई कर व्यवस्था अपनाने वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये किया गया
- पारिवारिक पेंशन पर छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया
- नई व्यवस्था के तहत 58 प्रतिशत से अधिक कॉरपोरेट टैक्स प्राप्तियां संग्रहित की गई
- व्यक्तिगत करदाताओं में से दो तिहाई करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था को अपनाया
- स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने के क्रम में सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त किया गया
- निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया गया
- कई तरह के भुगतानों पर लगने वाले 5 प्रतिशत टीडीएस का विलय 2 प्रतिशत टीडीएस में किया गया
- निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष किया गया
- एक्स-रे पैनल, मोबाइल फोन तथा पीसीबीए पर सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया
- सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं सस्ती होंगी, सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया गया ■

बजट 2024–25 के बारे में प्रधानमंत्री के विचार

केंद्रीय बजट 2024-25 समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना की। केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा। यह गांवों के गरीब किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाएगा। 25 करोड़ लोगों के गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने के बाद एक नव-मध्यम वर्ग के उभरने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट उनके सशक्तीकरण में निरंतरता जोड़ता है और रोजगार के अनगिनत अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस बजट से शिक्षा और कौशल विकास को नया आयाम मिलेगा। श्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि यह बजट मध्यम वर्ग, जनजातीय समाज, दलित और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस साल का बजट महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा और साथ ही, इससे छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के लिए प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट विनिर्माण पर भी बल देता है, बुनियादी ढांचे पर भी बल देता है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह निरंतरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को नई ताकत देगा।

1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना

रोजगार और स्वरोजगार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने पीएलआई योजना की सफलता का उल्लेख किया और रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को रेखांकित किया, जिससे रोजगार के करोड़ों नए अवसरों का सृजन होगा। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा का पहला वेतन सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने उच्च शिक्षा के प्रावधानों और 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की योजना का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि योजना के तहत देश की शीर्ष कंपनियों में काम करने वाले युवा प्रशिक्षुओं के सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे।

हर शहर, हर गांव और हर घर में उद्यमी तैयार करने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने मुद्रा ऋण के तहत बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का उल्लेख किया, जिससे छोटे कारोबारियों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और वंचितों को काफी लाभ मिलेगा।

भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने एमएसएमई के देश के मध्यम वर्ग से जुड़े होने और गरीब तबके के लिए रोजगार की संभावनाओं पर जोर दिया। श्री मोदी ने छोटे उद्योगों को बड़ी ताकत देने के लिए बजट में घोषित नई योजना के बारे में जानकारी दी, जिससे एमएसएमई के लिए ऋण की सुगमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बजट में की गई घोषणाएं विनिर्माण और निर्यात को हर जिले तक ले जाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि ई-कॉमर्स, निर्यात केंद्र और खाद्य गुणवत्ता परीक्षण एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम को नई गति देंगे।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम के लिए अनेक अवसर लेकर आया है। उन्होंने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के कोष और एंजल टैक्स को खत्म करने के उदाहरण दिए।

राष्ट्र की विकास यात्रा में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार: जगत प्रकाश नड्डा

यह बजट केवल एक दस्तावेज नहीं है; यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत@47' के विजन की ओर ले जाने वाला एक रोडमैप है, जो भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

यह सावधानीपूर्वक तैयार किया गया दूरदर्शी बजट हमारे राष्ट्र की विकास यात्रा में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को परिभाषित करते हुए यह बजट प्रगति को गति देने और समावेशी विकास प्रदान करने का वादा करता है। यह बजट युवाओं और महिलाओं से लेकर किसानों एवं वंचितों तक सभी के लिए अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समाज का हर वर्ग हमारी साझा प्रगति से लाभान्वित हो।

हमारे राष्ट्रीय विजन और विकास योजनाओं को बड़ी दूरदर्शिता के साथ दर्शाने वाला बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को मेरी हार्दिक बधाई। ■

12 नए औद्योगिक नोड्स, नए सैटेलाइट टाउन और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट योजना

श्री मोदी ने 12 नए औद्योगिक नोड्स, नए सैटेलाइट टाउन और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि रिकॉर्ड हाई कैपेक्स अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे देश में नए आर्थिक केंद्रों का विकास संभव होगा और बहुत बड़ी संख्या में नए रोज़गार बनेंगे।

रिकॉर्ड रक्षा निर्यात पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति दुनिया का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है, जिससे पर्यटन उद्योग के लिए नई संभावनाएं बनी हैं। उन्होंने इस वर्ष के बजट में पर्यटन पर जोर दिए जाने को रेखांकित करते हुए कहा कि पर्यटन उद्योग गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए अनेक अवसर लेकर आता है।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार कर में राहत मिलती रहे, जबकि इस साल के बजट में आयकर में कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी और टीडीएस नियमों को सरल बनाने के फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से करदाताओं को अधिक पैसे बचाने में मदद मिलेगी।

भारत के पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति

श्री मोदी ने कहा कि 'पूर्वोदय' के विजन के माध्यम से भारत के पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं जैसे राजमार्गों, जल परियोजनाओं और बिजली परियोजनाओं का निर्माण कर विकास को नई गति दी जाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि इस बजट का बहुत बड़ा फोकस देश के किसान हैं। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना के

मुख्य बिंदु

- 'विकसित भारत' के लिए बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करता है, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है
- सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है, इससे रोजगार के करोड़ों नए अवसरों का सृजन होगा
- इस बजट से शिक्षा और कौशल विकास को नया आयाम मिलेगा
- हम हर शहर, हर गांव और हर घर में उद्यमी तैयार करेंगे
- पिछले 10 वर्षों में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार कर में राहत मिलती रहे
- यह बजट स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लाया है
- इस बजट का बहुत बड़ा फोकस देश के किसान हैं
- आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर लेकर आया है, यह बेहतर विकास और उज्ज्वल भविष्य लाया है
- आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा और 'विकसित भारत' की ठोस नींव रखेगा

यह बजट मांग को बढ़ावा देगा और नए अवसर पैदा करेगा: राजनाथ सिंह

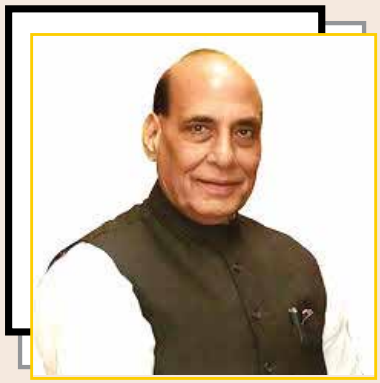

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक बेहतरीन बजट पेश करने के लिए बधाई! यह बजट एक समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में मदद करेगा, साथ ही समावेशी एवं तेज गति वाले विकास के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन से प्रेरित यह बजट भारत के आर्थिक विकास को गति देगा। यह बजट कई मायनों में अनूठा है और इसमें सर्वांगीण एवं समावेशी विकास के लिए एनडीए सरकार की 9 प्रमुख प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। इस बजट के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को मजबूती प्रदान की गयी है। यह बजट 2027 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है। बुनियादी ढांचे, कृषि, बैंकिंग, ऊर्जा, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास, एमएसएमई और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट मांग को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाएगा। मैं भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास गति देने के लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। ■

बजट युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों की एक नई दुनिया खोलेगा: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बजट 2024-25 की सराहना करते हुए इसे जनहितैषी एवं विकास हितैषी बताया। श्री शाह ने इस दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बहुत-बहुत बधाई दी।

एक्स प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट की एक शृंखला में श्री शाह ने कहा कि बजट 2024-25 मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार का देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है।

उन्होंने कहा कि बजट 2024-25 भारत की आर्थिक वृद्धि को देश की युवा शक्ति के साथ जोड़ने के लिए इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इसमें 4.10 करोड़ युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशाल कोष उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का इन अभूतपूर्व पहल के लिए धन्यवाद, जो युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों की एक नई दुनिया खोलेंगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नारी शक्ति के सामर्थ्य व हौसले को नई ऊंचाई देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है और इस बजट में Women-led development को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन इसका प्रतिबिंब है। ■

बाद अब सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं, जिससे किसानों और मध्यम वर्ग दोनों को मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए, दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है।

गरीबों के लिए 3 करोड़ घर

गरीबी उन्मूलन और गरीबों के सशक्तीकरण से जुड़ी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए 3 करोड़ घरों और जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के बारे में जानकारी दी, जो संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ 5 करोड़ जनजातीय परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा, ग्राम सड़क योजना 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ेगी, जिसका लाभ सभी राज्यों को मिलेगा।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर लेकर आया है। यह बेहतर विकास और उज्ज्वल भविष्य लाया है। प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने और 'विकसित भारत' की ठोस नींव रखने की बजट की क्षमता को रेखांकित करते हुए अपनी बात समाप्त की। ■

आर्थिक समीक्षा 2023-24 : प्रमुख बातें

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को संसद में 'आर्थिक समीक्षा 2023-24' पेश की। आर्थिक समीक्षा की प्रमुख बातें निम्न हैं:

अध्याय 1 : आर्थिक स्थिति – स्थिरता निरंतर बरकरार है

- आर्थिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जोखिम काफी हद तक संतुलित हैं, यह भी सच्चाई है कि बाजार उम्मीदें काफी ज्यादा हैं।
- अनेक तरह की विदेशी चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2023 में हासिल की गई भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की तेज गति वित्त वर्ष 2024 में भी बरकरार रही। वृहद् आर्थिक स्थिरता पर फोकस करने से यह सुनिश्चित हुआ कि विदेशी चुनौतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा।
- भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में 8.2 प्रतिशत रही, वित्त वर्ष 2024 की चार तिमाहियों में से तीन तिमाहियों में विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक रही।
- आपूर्ति के मोर्चे पर सकल मूल्य वर्द्धित (जीवीए) की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में 7.2 प्रतिशत (2011-12 के मूल्यों पर) रही और स्थिर मूल्यों पर शुद्ध कर संग्रह वित्त वर्ष 2024 में 19.1 प्रतिशत बढ़ गया।
- चालू खाता घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7 प्रतिशत रहा, जो कि वित्त वर्ष 2023 में दर्ज किए गए जीडीपी के 2.0 प्रतिशत के सीएडी से काफी कम है।
- महामारी से उबरने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रमबद्ध ढंग से विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक रही, यह उपलब्धि केवल कुछ प्रमुख देशों ने ही हासिल की है।
- कुल कर संग्रह का 55 प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से और शेष 45 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ।
- सरकार 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने में सक्षम रही है। पूंजीगत खर्च के लिए आवंटित कुल व्यय में लगातार वृद्धि की गई है।

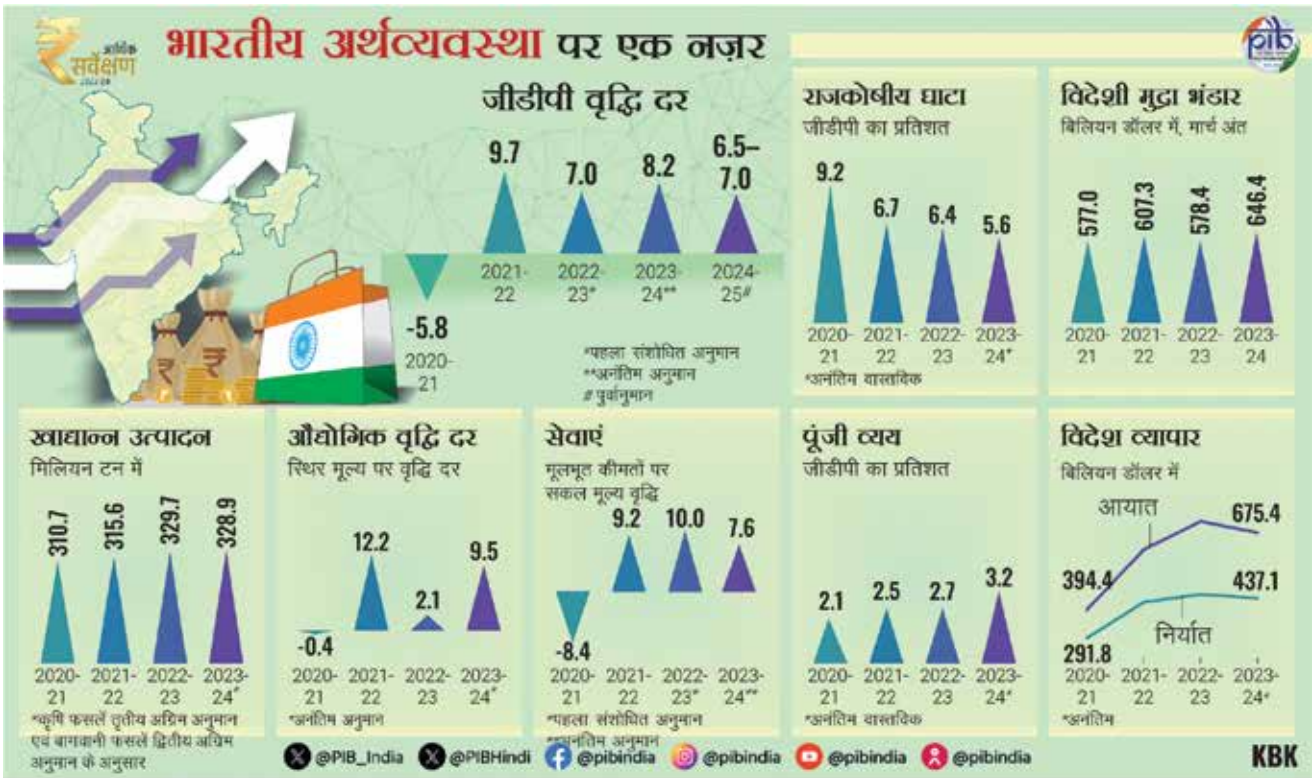

अध्याय 2 : मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता – स्थिरता पर फोकस है

- भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2024 में दमदार प्रदर्शन किया है।
- कुल मिलाकर महंगाई दर के नियंत्रण में रहने के परिणामस्वरूप आरबीआई ने पूरे वित्त वर्ष के दौरान नीतिगत दर को यथावत रखा।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्त वर्ष 2024 में पॉलिसी रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा। विकास की गति तेज करने के साथ-साथ महंगाई दर को धीरे-धीरे तय लक्ष्य के अनुरूप किया गया।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कर्ज वितरण मार्च, 2024 के आखिर में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 164.3 लाख करोड़ रुपये रहा।
- एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी के विलय के प्रभाव को छोड़कर ब्रॉड मनी (एम3) की वृद्धि दर 22 मार्च, 2024 को 11.2 प्रतिशत थी (सालाना आधार पर), जबकि एक साल पहले यह वृद्धि दर 9 प्रतिशत ही थी।
- बैंक कर्ज दहाई अंकों में बढ़ गए, जो कि काफी व्यापक रहे, सकल एवं शुद्ध गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां यानी फंसे कर्ज कई वर्षों के न्यूनतम स्तर पर रहे, बैंक परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का बढ़ना यह दर्शाता है कि सरकार मजबूत एवं स्थिर बैंकिंग क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्ध है।
- कर्जों में वृद्धि अब भी दमदार है, सेवाओं के लिए दिए गए कर्जों और पर्सनल लोन का इसमें मुख्य योगदान रहा है।
- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को मिले कर्ज वित्त वर्ष 2024 के दौरान दहाई अंकों में बढ़ गए।
- औद्योगिक कर्जों की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले यह वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत ही थी।
- आईबीसी को पिछले 8 वर्षों में ट्विन बैलेंस शीट समस्या का प्रभावकारी समाधान माना गया है। मार्च, 2024 तक 13.9 लाख करोड़ रुपये के मूल्य वाले 31,394 कॉरपोरेट कर्जदारों के मामले निपटाए गए।
- प्राथमिक पूंजी बाजारों में वित्त वर्ष 2024 के दौरान 10.9 लाख करोड़ रुपये का पूंजी सृजन हुआ (यह वित्त वर्ष 2023 के दौरान निजी और सरकारी कंपनियों के सकल स्थिर पूंजी सृजन का लगभग 29 प्रतिशत है)
- भारतीय शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण काफी ज्यादा बढ़ गया है, बाजार पूंजीकरण-जीडीपी अनुपात पूरी दुनिया में पांचवें सर्वाधिक स्तर पर रहा।
- वित्तीय समावेश केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने, असमानता में कमी करने और गरीबी उन्मूलन में भी मददगार है। अगली बड़ी चुनौती डिजिटल वित्तीय समावेश (डीएफआई) है।
- कर्जों को बैंकिंग सहारे का वर्चस्व धीरे-धीरे कम हो रहा है और पूंजी बाजारों की भूमिका बढ़ रही है। चूंकि भारत के वित्तीय क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसे संभावित असुरक्षा या खतरों से निपटने के लिए अवश्य ही तैयार रहना चाहिए।
- भारत आने वाले दशक में सबसे तेजी से विकसित होने वाले बीमा बाजारों में से एक रहेगा।
- भारत का माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के रूप में उभरा है।

अध्याय 3 : कीमतें और महंगाई – नियंत्रण में

- केन्द्र सरकार द्वारा समय पर उठाए गए नीतिगत कदमों और भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य स्थिरता संबंधी उपायों से खुदरा महंगाई दर को 5.4 प्रतिशत पर बरकरार रखने में मदद मिली, जो कि महामारी से लेकर अब तक की अवधि में न्यूनतम स्तर है।
- केन्द्र सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप ईंधन की खुदरा महंगाई दर वित्त वर्ष 2024 में निम्न स्तर पर टिकी रही।
- अगस्त, 2023 में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत देश के समस्त बाजारों में प्रति सिलेंडर 200 रुपये घटा दी गई। उसके बाद से ही एलपीजी की महंगाई अवस्फीति के दायरे में चली गई है।
- इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रति लीटर 2 रुपये घटा दीं। इसके परिणामस्वरूप वाहनों में उपयोग होने वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा महंगाई भी अवस्फीति के दायरे में चली गई है।
- भारत की नीति कई चुनौतियों से सफलतापूर्वक गुजरी जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित हुई।
- कोर सेवाओं की महंगाई दर घटकर वित्त वर्ष 2024 में पिछले नौ वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गई, इसके साथ ही कोर वस्तुओं की महंगाई दर भी घटकर पिछले चार वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गई।
- उद्योगों को प्रमुख इनपुट सामग्री की आपूर्ति बेहतर होने से वित्त वर्ष 2024 में प्रमुख उपभोक्ता उपकरणों की महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई।
- मौसमी प्रभावों, जलाशयों के जलस्तर में कमी तथा फसलों के नुकसान के कारण कृषि क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनसे कृषि उपज और खाद्यानों की कीमत पर असर पड़ा। वित्त वर्ष 2023 में खाद्य महंगाई दर 6.6 प्रतिशत थी, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई।
- सरकार ने उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई की, जिनमें स्टॉक प्रबंधन, खुला बाजार संचालन, आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए सब्सिडी का प्रावधान और व्यापार नीति उपाय शामिल हैं। इनसे खाद्य महंगाई दर को कम करने में मदद मिली।
- 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने वित्त वर्ष 2024 में महंगाई दर

6 प्रतिशत से कम रही।

- इसके अलावा, उच्च महंगाई दर वाले राज्यों में ग्रामीण-शहरी महंगाई दर अंतर अधिक रहा, जहां ग्रामीण महंगाई दर शहरी महंगाई दर से अधिक रही।
- रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर कम होकर क्रमशः 4.5 और 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह माना गया है कि मॉनसून सामान्य रहेगा और कोई बाहरी या नीतिगत बाधाएं नहीं आएंगी।
- आईएमएफ ने भारत के लिए महंगाई दर को 2024 में 4.6 प्रतिशत और 2025 में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

अध्याय 4 : बाहरी क्षेत्र – बहुतायत में स्थिरता

- मुद्रास्फीति तथा भू-राजनीतिक बाधाओं के बावजूद भारत के बाह्य क्षेत्र में मजबूती बनी रही।
- दुनिया के 139 देशों में भारत की स्थिति विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में छह पायदान बेहतर हुई। भारत की स्थिति 2018 के 44वें स्थान से बेहतर होकर 2023 में 38वें पायदान पर पहुंच गई।
- व्यापारिक आयात में कमी और सेवा निर्यात वृद्धि ने चालू खाता घाटे में सुधार किया है, जो वित्त वर्ष 2024 में घटकर 0.7 प्रतिशत रह गया है।
- वैश्विक वस्तु एवं सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। वैश्विक वस्तु निर्यात में देश की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 1.8 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान यह हिस्सेदारी औसतन 1.7 प्रतिशत रही थी।
- भारत के सेवा निर्यात में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 2024 में 341.1 बिलियन डॉलर रही। इस वृद्धि का कारण मुख्य रूप से आईटी/सॉफ्टवेयर तथा अन्य व्यापार सेवाएं थीं।
- भारत वैश्विक स्तर पर विदेशों से सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश रहा, जो 2023 में 120 बिलियन डॉलर की सीमा को पार कर गया।
- भारत का बाहरी ऋण पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है, मार्च, 2030 के अंत में जीडीपी अनुपात में बाहरी ऋण 18.7 प्रतिशत था।

अध्याय 5 : मध्य अवधि दृष्टिकोण – न्यू इंडिया के लिए विकास रणनीति

- लघु से मध्यम अवधि के लिए नीतिगत विशेष ध्यान के प्रमुख क्षेत्र हैं– रोजगार और दक्षता निर्माण, कृषि क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग, एमएसएमई की बाधाओं का समाधान, ऊर्जा बदलाव के लिए हरित स्रोतों को अपनाने का प्रबंधन, चीन की पहली को कुशलतापूर्वक सुलझाने का प्रयास, कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करना, असमानता को दूर करना तथा हमारे युवाओं के स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करना।

- 7 प्रतिशत से अधिक की दर पर भारत में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।

अध्याय 6 : जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को अपनाना – बाधाओं का समाधान

- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट में जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जी-20 समूह का एकमात्र ऐसा देश है, जहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि की संभावना है।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के संदर्भ में भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- 31 मई, 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4 हो गई है।
- इसके अलावा, देश ने अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कम किया है, जिसमें 2005 के स्तर पर 2019 में 33 प्रतिशत की कमी आई है।
- भारत की जीडीपी 2005 से 2019 के बीच लगभग 7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ी है, जबकि उत्सर्जन की वृद्धि 4 प्रतिशत के सीएचजीआर से बढ़ी है।
- सरकार ने कई स्वच्छ कोयला पहलों की शुरुआत की है, जिसमें कोयला गैसीकरण मिशन भी शामिल है।
- विगत पांच वर्षों में ईपीएफओ के तहत निवल पे-रोल में दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है, जोकि वित्त वर्ष 19 में 61.1 लाख कर्मचारियों की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 131.5 लाख हुई।
- ईपीएफओ में वित्त वर्ष 15 और 24 के बीच सदस्यों की संख्या में

8.4 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

- विनिर्माण क्षेत्र में एआई का प्रभाव कम, क्योंकि औद्योगिक रोबोट मानव की तुलना में न तो सशक्त हैं और न ही किफायती।
- गिग कार्यबल का 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान।
- भारतीय अर्थव्यवस्था को गैर-कृषि क्षेत्र में 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 78.5 लाख नौकरी उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे श्रम शक्ति में वृद्धि की जा सके।
- देश में 2022 में 50.7 करोड़ लोगों की देखभाल की तुलना में 2050 में 64.7 करोड़ लोगों की देखभाल की आवश्यकता होगी।
- सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश से 11 मिलियन रोजगार सृजन होने की संभावना है, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं को मिलेंगी।
- 51 मिलियन टन तेल के बराबर कुल वार्षिक ऊर्जा बचत सालाना 1,94,320 करोड़ रुपये की बचत के समान है और इससे करीब 306 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी आएगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन विस्तार से भूमि और जल की मांग बढ़ेगी।
- सरकार ने जनवरी-फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ रुपये और उसके बाद अक्तूबर-दिसम्बर 2023 में 20,000 हजार करोड़ रुपये के सावरेन हरित बॉन्ड जारी किए।

अध्याय 7 : सामाजिक क्षेत्र – लाभ जो सशक्त बनाते हैं

- नये कल्याणकारी दृष्टिकोण खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का प्रभाव बढ़ाने पर केन्द्रित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सुशासन का डिजिटलीकरण कल्याणकारी कार्यक्रम पर खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का प्रभाव कई गुना बढ़ाने वाला है।
- वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2024 के बीच बाजार मूल्य आधारित जीडीपी करीब 9.5 प्रतिशत की संचित वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ी है, जबकि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च 12.8 प्रतिशत संचित वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ा है।
- असमानता का संकेतक, गिनी कोइफिशियंट, देश के ग्रामीण क्षेत्र के मामले में 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्र के मामले में 0.363 से 0.314 पर आ गए।
- 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाये गए और योजना के तहत अस्पतालों में भर्ती 7.37 करोड़ मरीजों को कवर किया गया।
- बौद्धिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की चुनौती आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 बौद्धिक बीमारियों को कवर किया गया।
- बच्चों की शुरुआती शिक्षा के 'पोषण भी पढ़ाई भी' कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ी केन्द्रों में विश्व का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता प्री-स्कूल नेटवर्क विकसित करना है।

- स्वैच्छिक योगदान और सामुदायिक मेलजोल के माध्यम से विद्यांजलि पहल ने 1.44 करोड़ से अधिक छात्रों के शैक्षणिक अनुभव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उच्च शिक्षा में सभी वर्गों की महिलाओं के दाखिले में तेज वृद्धि हुई है, साथ ही एससी/एसटी और ओबीसी जैसे पिछड़े वर्गों की संख्या बढ़ने से वित्त वर्ष 2015 से 31.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।
- वित्त वर्ष 2024 में करीब एक लाख पेटेंट प्रदान किए जाने के साथ भारत में अनुसंधान एवं विकास में तीव्र प्रगति हो रही है। इससे पहले वित्त वर्ष 2020 में 25,000 से भी कम पेटेंट प्रदान किए गए थे।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में 3.10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो कि वित्त वर्ष 2014 (बजट अनुमान) की तुलना में 218.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- पीएम-आवास-ग्रामीण के तहत पिछले नौ साल में (10 जुलाई, 2024 की स्थिति के अनुसार) गरीबों के लिए 2.63 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया।
- ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2014-15 से (10 जुलाई, 2024 की स्थिति के अनुसार) 15.14 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया।

अध्याय 8 : रोजगार और कौशल विकास – गुणवत्ता की ओर

- वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2 प्रतिशत पर आने से भारतीय श्रमिक बाजार संकेतक में पिछले छह साल के दौरान सुधार आया है।
- 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों के मामले में तिमाही शहरी बेरोजगारी दर मार्च, 2024 में समाप्त तिमाही के दौरान एक साल पहले इसी तिमाही की 6.8 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई।

- पीएलएफएस के अनुसार 45 प्रतिशत से अधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में, 11.4 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में, 28.9 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में और 13.0 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र में नियुक्त है।
- पीएलएफएस के अनुसार (15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में) युवा बेराजगारी दर 2017-18 के 17.8 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 10 प्रतिशत पर आ गई।
- ईपीएफओ पे-रोल में शामिल नये सब्सक्राइबर में करीब दो-तिहाई 18 से 28 वर्ष के आयुवर्ग से थे।
- लैंगिक परिपेक्ष में महिला श्रमिक बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) छह साल से बढ़ रही है।
- एएसआई 2021-22 के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार दर सुधर कर महामारी पूर्व के स्तर से ऊपर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही प्रति कारखाना रोजगार महामारी पूर्व के स्तर से बढ़ा है।
- वित्त वर्ष 2015 से 2022 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कामगार वेतन में शहरी क्षेत्रों के 6.1 प्रतिशत सीएजीआर के मुकाबले 6.9 प्रतिशत सीएजीआर वृद्धि हुई है।
- 100 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त कराने वाले कारखानों की संख्या वित्त वर्ष 2018 के मुकाबले 2022 में 11.8 प्रतिशत बढ़ी है।
- बड़े कारखानों (100 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति वाले) में छोटे कारखानों के मुकाबले रोजगार के अवसर बढ़े हैं, इससे विनिर्माण इकाइयों के उन्नयन की दिशा में संकेत मिलता है।

अध्याय 9 : कृषि और खाद्य प्रबंधन – यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है

- कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने पिछले पांच वर्षों में स्थिर मूल्यों पर 4.18 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है।
- भारतीय कृषि के संबद्ध क्षेत्र लगातार मजबूत विकास केंद्रों और कृषि आय में सुधार के लिए आशाजनक स्रोतों के रूप में उभर रहे हैं।
- 31 जनवरी, 2024 तक कुल कृषि भुगतान 22.84 लाख करोड़ रुपए।
- 31 जनवरी, 2024 तक बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ रुपये की 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया।
- वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान न्यूनतम जल अधिकतम फसल (पीडीएमसी) के तहत देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 90.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- अनुमान है कि शिक्षा सहित कृषि अनुसंधान में लगाए गए प्रत्येक रुपये से 13.85 रुपये का प्रतिफल।

अध्याय 10 : उद्योग – मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य

- वित्त वर्ष 2024 में 8.2 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि को 9.5 प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला।
- विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं में अनेक बाधाओं के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले दशक में 5.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। विकास के प्रमुख संचालक रसायन, लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर, परिवहन उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और उपकरण हैं।
- पिछले पांच वर्षों में कोयला के उत्पादन में तेजी आई है, जिससे आयात निर्भरता में कमी हुई है।
- भारत का फार्मास्युटिकल बाज़ार, जिसका वर्तमान मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, अपनी मात्रा के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है।
- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता है और शीर्ष पांच निर्यातक देशों में से एक है।
- भारत के इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र की वित्त वर्ष 22 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का अनुमानित 3.7 प्रतिशत है।
- भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मई, 2024 तक 1.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पीएलआई योजना के अंतर्गत 10.8 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन/बिक्री और 8.5 लाख से अधिक का रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) हुआ।
- उद्योगों को अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा कार्यबल के सभी स्तरों पर सुधार को उद्योग और अकादमी के बीच सक्रिय सहयोग के माध्यम से प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

अध्याय 11 : सेवाएं – विकास के अवसरों को बढ़ावा देना

- सेवा क्षेत्र भारत की प्रगति में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जो वित्त वर्ष 24 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55 प्रतिशत है।
- सेवा क्षेत्र में सर्वोच्च संख्या में सक्रिय कंपनियां (65 प्रतिशत) हैं, 31 मार्च, 2024 तक भारत में कुल 16,91,495 सक्रिय कंपनियां थीं।
- वैश्विक स्तर पर भारत का सेवा निर्यात 2022 में दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4 प्रतिशत था।
- भारत के सेवा निर्यात में कम्प्यूटर सेवा और व्यापार सेवा निर्यात का हिस्सा 73 प्रतिशत, वित्त वर्ष 24 में इसमें 9.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
- डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी 2019 के 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 6 प्रतिशत हो गई।
- वित्त वर्ष 24 में भारतीय हवाई यात्रियों की संख्या में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ भारत के विमानन क्षेत्र में अच्छी प्रगति दर्ज की है।
- वित्त वर्ष 24 में भारतीय हवाई अड्डों पर एयर कार्गो का रखरखाव

सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 33.7 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया।

- वित्त वर्ष 24 की समाप्ति मार्च, 2024 में 45.9 लाख करोड़ रुपये के सेवा सेक्टर ऋण के बकाया से हुई, जिसमें वर्ष दर वर्ष 22.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- भारतीय रेल में यात्री यातायात पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 24 में लगभग 5.2 प्रतिशत बढ़ा।
- राजस्व अर्जन मालभाड़ा ने (कोणकन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को छोड़कर) पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 24 में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- पर्यटन उद्योग ने वर्ष दर वर्ष 43.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2023 में 92 लाख विदेशी पर्यटकों के आगमन को देखा।
- 2023 में आवासीय रियल स्टेट देश में बिक्री वर्ष दर वर्ष 33 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2013 के बाद से सबसे ज्यादा थी और शीर्ष के आठ नगरों में कुल 4.1 लाख मकानों की बिक्री हुई।
- भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है और यह वित्त वर्ष 15 में एक हजार केंद्रों से वित्त वर्ष 23 तक 1,580 केंद्रों से भी अधिक हो गए हैं।
- भारत के ई-वाणिज्य उद्योग का 2030 तक 350 अरब अमरीकी डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है।
- कुल टेली-डेंसिटी (100 लोगों की आबादी पर टेलीफोनों की संख्या) देश में मार्च, 2014 में 75.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2024 में 85.7 प्रतिशत हो गई है। इंटरनेट डेंसिटी भी मार्च, 2024 में 68.2 प्रतिशत तक बढ़ गई।
- 31 मार्च, 2024 तक 6,83,175 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाए गए हैं, जिसने भारतनेट चरण-1 और चरण-2 में कुल 2,06,709 ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया है।
- दो महत्वपूर्ण बदलाव भारत के सेवा परिदृश्य को फिर से आकार दे रहे हैं– घरेलू सेवा डिलिवरी का तीव्र प्रौद्योगिकी निर्देशित बदलाव और भारत के सेवा निर्यात का विविधीकरण।

अध्याय 12 : अवसंरचना – संभावित वृद्धि को बढ़ाना

- हालिया वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में काफी वृद्धि ने बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की औसत रफ्तार वित्त वर्ष 14 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन करीब 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 24 तक प्रतिदिन करीब 34 किलोमीटर हो गई।
- रेल संबंधी पूंजीगत व्यय पिछले 5 वर्षों में नई लाइनों गेज परिवर्तन और लाइनों के दोहरीकरण के निर्माण में अच्छे खासे निवेश के साथ 77 प्रतिशत बढ़ गया है।
- भारतीय रेल वित्त वर्ष 25 में वंदे मेट्रो ट्रेनसेट कोच शुरु करेगी।
- वित्त वर्ष 24 में 21 हवाई अड्डों पर नई टर्मिनल इमारतें चालू की

गई हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता में वृद्धि हुई है और यह प्रतिवर्ष करीब 620 लाख यात्रियों तक पहुंच गई है।

- भारत का दर्जा विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक के अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट कैटगरी में 2014 में 44वें स्थान से 2023 में 22वें स्थान पर हो गया है।
- भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2014 और 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ रुपये (102.4 अरब अमरीकी डॉलर) का नया निवेश हुआ है।

अध्याय 13 : जलवायु परिवर्तन और भारत – हमें क्यों इस समस्या को अपनी नजरों से देखना चाहिए

- जलवायु परिवर्तन के लिए वर्तमान वैश्विक रणनीतियां त्रुटिपूर्ण हैं और सार्वभौमिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है।
- पश्चिम का जो दृष्टिकोण समस्या की जड़ यानी अत्यधिक खपत का समाधान नहीं निकालना चाहता, बल्कि अत्यधिक खपत को हासिल करने के दूसरे विकल्प चुनना चाहता है।
- 'एक उपाय सभी के लिए सही', काम नहीं करेगी और विकासशील देशों को अपने रास्ते चुनने की छूट दिए जाने की जरूरत है।
- भारतीय लोकाचार प्रकृति के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंधों पर जोर देते हैं, इसके विपरीत विकसित देशों में अत्यधिक खपत की संस्कृति को अहमियत दी जाती है।
- 'कई पीढ़ियों वाले पारंपरिक परिवारों' पर जोर से टिकाऊ आवास की ओर मार्ग प्रशस्त होगा।
- 'मिशन लाइफ' अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देने के मानवीय स्वभाव पर जोर देती है। अत्यधिक खपत वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या की जड़ है। ■

प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर लद्दाख का दौरा किया

"कारगिल में हमने न केवल युद्ध जीता, बल्कि सत्य, संयम और शक्ति का अविश्वसनीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 जुलाई को 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह श्रद्धांजलि समारोह में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने गौरव गाथाः एनसीओ द्वारा कारगिल युद्ध पर ब्रीफिंग सुनी और अमर संस्मरणः हट ऑफ रिमेंबरेंस का दौरा किया। उन्होंने वीरभूमि का भी दौरा किया।

श्री मोदी ने वर्चुअल तरीके लद्दाख में शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट का पहला विस्फोट भी देखा। शिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किमी लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निमू-पदुम-दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। काम पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुन ला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी।

श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की गौरवशाली भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की साक्षी है। श्री मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर होता है।

प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध के दिनों को याद करते हुए कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि उस समय सैनिकों के बीच थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी याद है कि कैसे हमारे सैनिकों ने इतनी ऊंचाई पर एक कठिन ऑपरेशन को अंजाम दिया था।

श्री मोदी ने कहा कि कारगिल में हमने न केवल युद्ध जीता, बल्कि हमने 'सच्चाई, संयम और ताकत' का एक अविश्वसनीय उदाहरण भी पेश किया। प्रधानमंत्री ने उस समय पाकिस्तान के धोखे पर प्रकाश डाला, जब भारत शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा कि सच्चाई से झूठ और आतंक को घुटनों पर ला दिया गया।

पाकिस्तान को हमेशा हार का सामना करना पड़ा

आतंकवाद की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को अतीत में हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। श्री मोदी ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा है और प्रासंगिक बने रहने के लिए आतंकवाद और छद्म युद्ध की आड़ में युद्ध जारी रखा है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवादियों के नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर जवान सभी आतंकी प्रयासों को रौंद देंगे।

श्री मोदी ने दोहराया कि भारत विकास के रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों पर काबू पा लेगा, चाहे वह लद्दाख हो या जम्मू-कश्मीर। उन्होंने याद दिलाया कि अब से कुछ ही दिनों में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल पूरे हो जाएंगे और आज का जम्मू-कश्मीर सपनों से भरे एक नए भविष्य की बात कर रहा है। श्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर में प्रगति का उदाहरण दिया और वहां जी-20 बैठकें आयोजित करने, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने, सिनेमा हॉल खोलने और साढ़े तीन दशकों के बाद ताजिया जुलूस शुरू करने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पृथ्वी का यह स्वर्ग तेजी से शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

श्री मोदी ने लद्दाख में हो रहे विकास को रेखांकित करते हुए कहा कि शिंकुन ला टनल के माध्यम से जम्मू-कश्मीर पूरे साल, हर मौसम में पूरे देश से जुड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि यह सुरंग लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी।

श्री मोदी ने लद्दाख के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह सुरंग उनके जीवन को और आसान बनाएगी, क्योंकि क्षेत्र में खराब मौसम के कारण उनके सामने आने वाली कई कठिनाइयां कम हो जाएंगी। ■

देश की रक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदीजी ने किया है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली स्थित भाजपा केन्द्रीय कार्यालय में कारगिल विजय रजत जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले लेफ्टिनेंट जे.एस. नैन (रिटायर्ड), कर्नल श्री वी.एन. थापर (रिटायर्ड) सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी देश के हर जिले में कारगिल विजय दिवस मनाकर भारत की सेना के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में कारगिल विजय दिवस मना रहा है। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज कारगिल विजय दिवस का 25वां वर्ष है। आज से 25 वर्ष पहले यह विजय हासिल की गई थी। यह विजय किसी पहाड़ी पर तिरंगे की जीत नहीं थी, बल्कि भारत के शौर्य और अस्मिता की जीत थी। भारतीय सेना के जांबाजों ने अपनी जान की आहुति देकर देश की रक्षा की है।

उन्होंने कहा कि यह देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जानें कि यह किस तरह का युद्ध था। भारत का इतिहास रहा है कि भारत कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं करता, लेकिन यदि कोई भारत पर आक्रमण करता है तो उसे नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध किया, 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराके पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर कराया। कारगिल में भी भारत की फौज ने शौर्य दिखाते हुए विजय प्राप्त की। पाकिस्तान कारगिल में चोरों की तरह आकर टाइगर हिल पर बैठ गया था। भारत यह युद्ध विषम परिस्थितियों में लड़ रहा था। पाकिस्तान कारगिल की चोटियों पर था और भारत के वीर जवानों को पहाड़ पर चढ़कर उस दुर्गम चोटी पर कब्जा करना था। हमारे वीर जवान रुके नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और टाइगर हिल पर पहुंचकर तिरंगा लहराया। जब 1962 में चीन से और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो हमारे शहीद जवानों के कपड़े, टोपी और उनका पहचान पत्र तो घर आता था लेकिन जवान नहीं आता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलजी ने यह तय किया कि कोई भी जवान जो देश के लिए शहादत देता है, पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार उसके गांव में होगा और इनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार व भारतीय सेना लेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष ने फौज का उपयोग तो किया लेकिन जो स्थान देना चाहिए था, वो स्थान नहीं दिया। 1971 से 'वन रैंक-वन पेंशन' की मांग हो रही थी, पीढ़ियां निकाल गई, 40 वर्ष बीत गए लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर कांग्रेस की सरकार ने जाते-जाते 500 करोड़ रुपए का बजट लाकर 'वन रैंक-वन पेंशन' लाने का खोखला वादा कर दिया। 2014 में देश की जनता ने कांग्रेस को विदा कर दिया और भाजपा की सरकार को चुना। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू किया। देश के फौजी भाइयों को 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये देने का काम मोदी सरकार ने किया है।

उन्होंने कहा कि देश की रक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। आज भारत के पास स्वदेशी युद्धपोत हैं, जो देश के लिए गौरव का विषय है। आज भारत 88 हजार 319 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पाद दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और देश की फौज के नाम पर राजनीति नहीं करती है, देशहित सरकार के लिए सर्वोपरि है। दुनिया

की कई रिपोर्ट्स यह कहती हैं कि भारत की फौज और जवान होनी चाहिए, अग्निवीर उसी लक्ष्य को पूरा करने का एक रास्ता है। अग्निवीर के माध्यम से आज भारत में युवा फौज बन रही है जो फाइटिंग स्पिरिट के साथ देश की रक्षा करने का काम कर रही है। विपक्षी दलों के लिए देश की सुरक्षा भी राजनीति का विषय बन गई है और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वह देश को भूल गए हैं। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश सरकारें अग्निवीरों को रोजगार में पूरे अवसर प्रदान करेंगी, लेकिन कुछ लोग राजनीति करने के लिए देश की रक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के लोग जब देशभक्ति की बात करते हैं, तो वो वीर जवानों के घावों को ताजा करते हैं। भारत सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश की रक्षा के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध हैं। आज कारगिल विजय दिवस के दिन प्रधानमंत्रीजी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि 'न आंख उठा के बात करेंगे, न आंख झुका के बात करेंगे, बल्कि आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे'। श्री नड्डा ने आश्वासन दिया कि देश के वीर शहीदों की शहादत को कभी भूला नहीं जाएगा। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 'मशाल रैली' को संबोधित किया

'अगर पाकिस्तान उकसाने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा 25 जुलाई, 2024 को दिल्ली के कनॉट प्लेस में आयोजित मशाल रैली में सम्मिलित हुए और कारगिल युद्ध में विपरीत परिस्थितियों में देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर जवानों को याद करते हुए नमन किया। उन्होंने कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित मशाल रैली में भाग भी लिया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के पश्चात् प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं युवा मोर्चा प्रभारी श्री सुनील बंसल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या, राष्ट्रीय सचिव श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा सहित पार्टी के अन्य नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि 25 वर्ष पहले भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी और कल कारगिल विजय दिवस को रजत जयंती के रूप में मनाया जाएगा। कारगिल का विजय दिवस मनाकर हम भारत के उन वीर सपूतों को याद करेंगे जिनके शौर्य ने कारगिल पर पाकिस्तान के इरादों को चकनाचूर कर दिया था और भारत का झण्डा लहराया था। कारगिल का युद्ध एक विशेष परिस्थिति का युद्ध था। पाकिस्तान ने सीधी तरीके से आक्रमण नहीं किया था, बल्कि चोरों की तरह चुपके-चुपके पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल पर अड्डा जमाया था। लेफ्टिनेंट कालिया और विक्रम बत्रा जैसे शहीदों को याद करते हुए यह बात भी याद रखी जानी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी देश के जवानों ने ये लड़ाई लड़ी थी। दुश्मन कारगिल की चोटियों पर था और भारत के वीर जवानों को पहाड़ पर चढ़कर उस दुर्गम चोटी पर कब्जा करना था। यह बहुत ही कठिन कार्य था। हमारे वीर जवान रुके नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि लगातार योजनाबद्ध तरीके से लड़े और फिर से कारगिल की दुर्गम चोटियों पर तिरंगा लहराया।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उत्तर भारत के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और प्रभारी थे। उस समय भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कारगिल के युद्ध के दौरान वहां जाकर जवानों का उत्साहवर्धन किया था। श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने उस दौरान कहा था कि जो भी शहीद होगा, वो शहादत किसी परिवार की नहीं बल्कि देश की होगी। पूरे सम्मान के साथ उनके शरीर को लाया जाएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब 1962 में चीन से और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमारे शहीद जवानों के कपड़े, टोपी और उनका पहचान पत्र तो घर आता था लेकिन जवान नहीं आता था। प्रधानमंत्री अटल जी ने यह तय किया कि कोई भी जवान जो देश के लिए शहादत देता है, पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार उसके गांव में होगा और इनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार व भारतीय सेना लेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि जब यूपीए के कार्यकाल में रक्षामंत्री से पूछा गया कि आप सीमा पर सैनिकों के लिए सड़क क्यों नहीं बनवाते हैं? तो उत्तर दिया गया था कि सरकार की प्राथमिकता में इस कार्य के लिए पैसे नहीं हैं। पहले सीमा का काफिला वन-वे सड़क से जाता था, आज हमारी फौज सीमा तक जाने के लिए डबल-लेन सड़क और पक्के डबल-लेन पुलों का उपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बीते 10 वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे, 12 महीने चलने वाली सड़कों का निर्माण किया है। आज अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक भारतीय सेना डेढ़ दिन में पहुंच जाती है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भारतीय सेना के पास लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, बुलेटप्रूफ उपकरणों की भी कमी थी और रक्षा उपकरणों की कोई नई खरीद नहीं की गई थी। आज भारत न केवल अपने रक्षा उपकरण बनाता है, बल्कि इसे अन्य देशों को निर्यात भी कर रहा है। भारत आज लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों का भी निर्माण कर रहा है। यदि पाकिस्तान उरी और पुलवामा जैसी घटनाओं को दोहराने की कोशिश करेगा तो उसे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हर जिले में 'विजय ज्योति' जलाकर विजय दिवस मनाएगा, हमारे वीर सैनिकों का सम्मान करेगा और संदेश देगा कि 140 करोड़ लोगों का देश वीर जवानों के साथ खड़ा है। ■

भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अधिवेशन बैठक, पुणे

भाजपा की सफलता में प्रत्येक कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण योगदान होता है : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 जुलाई, 2024 को पुणे (महाराष्ट्र) में प्रदेश अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महायुति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। श्री शाह ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए कांग्रेस और शरद पवार की भी आलोचना की। बैठक के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले एवं मुंबई भाजपा अध्यक्ष श्री आशीष शेलार सहित अन्य नेता मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के मार्गदर्शन में देश भर में कार्यकारिणी बैठकें की जा रही हैं। हालांकि, महाराष्ट्र में इन प्रयासों का एक अलग फोकस एवं उद्देश्य है। राष्ट्रव्यापी कार्यकारिणी बैठकों का उद्देश्य भाजपा कार्यकर्ताओं को

आगामी चुनावों के लिए तैयार करना है। महाराष्ट्र में 2024 के चुनावों की समीक्षा एवं प्रदेश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में प्रत्येक कार्यकर्ता ने भाजपा की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन चुनावों के परिणामों से स्पष्ट हैः 60 वर्षों में पहली बार किसी नेता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और वह नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं। भाजपा को अब 2014 और 2019 की सफलताओं को आगे बढ़ाते हुए 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में और भी बड़ी जीत हासिल करने की दिशा में काम करना होगा। ■

दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश भाजपाध्यक्ष नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 25 जुलाई, 2024 को विधान परिषद् सदस्य डॉ. दिलीप जायसवाल को बिहार प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया।

संप्रति, श्री जायसवाल बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और सिक्किम प्रदेश भाजपा के प्रभारी भी हैं। ■

मदन राठौड़ बने राजस्थान प्रदेश भाजपाध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 25 जुलाई, 2024 को राज्यसभा सदस्य श्री मदन राठौड़ को राजस्थान प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री राठौड़ 2002-2008 और 2013-2018 के दौरान दो बार विधानसभा के सदस्य भी रहे। ■

संगठनात्मक नियुक्तियां

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 25 जुलाई, 2024 को विभिन्न राज्यों के प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों की नियुक्ति की। सूची इस प्रकार हैः

प्रदेश	प्रभारी	सह-प्रभारी
असम	श्री हरीश द्विवेदी	
चंडीगढ़	श्री अतुल गर्ग, सांसद	
लक्षद्वीप	श्री अरविन्द मेनन	
राजस्थान	डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, सांसद	श्रीमती विजया रहाटकर
तमिलनाडु	श्री अरविन्द मेनन	श्री सुधाकर रेड्डी
त्रिपुरा	डॉ. राजदीप रॉय	

भारतीय जनसंघ ही क्यों?

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

भारतीय जनसंघ के प्रथम वार्षिक अधिवेशन (कानपुर, 29 दिसंबर, 1952) में तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा दिए गए भाषण का द्वितीय भाग

प्रत्येक कार्य के अधीक्षण की पूर्ण व्यवस्था चाहिए और समय-समय पर उसकी प्रगति का पूरा विवरण जनता को प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार के सभी सार्वजनिक कार्यों का वातावरण नीचे से उपर तक सुव्यवस्था तथा सहकारिता से परिपूर्ण हो जिसका परिणाम ऊपर से नीचे तक सभी पर हो ताकि वे जनहितैषी राज्य की उच्चतम धारणाओं का योग्य रूप से प्रतिनिधित्व कर सकें। इस समय उत्पादन तथा वितरण की अनेक इकाइयां निजी व्यवस्था के द्वारा भी चलाई जा रही हैं। अनेक असुविधा के कारण वे अपनी पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हैं। यदि उन्हें राज्य की ओर से उचित सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त हो तो वह भी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि में तथा बेरोजगारी के बढ़ते हुए संकट को रोकने में सहायक हो सकती हैं।

विभाजन के पश्चात की समस्याओं में से तीन विषयों पर जनता का ध्यान हाल ही में बहुत अधिक केन्द्रित हुआ है। वे हैं काश्मीर, पूर्वी बंगाल और पुनर्वास की समस्या।

काश्मीर

काश्मीर के विषय में हमारे दल ने यह अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू तथा काश्मीर का पूरा राज्य भारत का अविभाज्य अंग है। आरंभ में सुरक्षा परिषद् में इस समस्या को ले जाने के कारण कुछ भी रहे हों, गत तीन वर्षों की घटनाएं यह बताती हैं कि इस प्रश्न को वहां से वापिस ले लेना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इस विषय में भारत सुरक्षा परिषद् से किसी भी प्रकार के न्याय की आशा नहीं कर सकता। यद्यपि पाकिस्तान काश्मीर की भूमि का आक्रांता है तो भी भारत के न्यायमुक्त अधिकार का समर्थन करने में एक विचित्र प्रकार की उदासीनता दिखाई देती है। इस प्रकार का आचरण कुछ महाशक्तियों द्वारा जान-बूझकर किया जा रहा है, जिनमें यू.एस.ए. और ब्रिटेन भी सम्मिलित हैं। कुछ समय पूर्व काश्मीर में बनी संविधान सभा को यह चुनौती दी जा चुकी है कि जहां तक जम्मू का सम्बन्ध है वह एक प्रतिनिधि संस्था नहीं है। यह होते हुए भी इस सभा को भारत में मिलने के प्रश्न को अन्तिम रूप से तय करना चाहिए। यह निर्णय हो जाने के पश्चात् दो प्रश्न ही प्रमुख रूप से

रह जायेंगे एक तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू तथा कश्मीर के प्रदेश के भविष्य के विषय में और दूसरे भारतीय संविधान के इस राज्य पर लागू होने के बारे में। प्रथम के सम्बन्ध में जम्मू-काश्मीर सहित सारे भारत का सम्मान यह मांग करता है कि शत्रु के हाथों से इस प्रदेश को छुड़ाने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए भारत को किसी भी परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। यदि एक बार भी हमने प्रदेश पर इस प्रकार बलात् अधिकार स्वीकार कर लिया तो भविष्य में हमारी स्वतंत्रता को भारी संकट खड़ा हो जायेगा।

दूसरे विषय के सम्बन्ध में हम अपने विचार पिछले अवसरों पर खुलकर प्रकट कर चुके हैं। हमारे इस मत के कारण भारत के कितने ही तथाकथित मित्रों और हितैषियों ने हमें गलत समझा है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जम्मू तथा काश्मीर का भारत के साथ विलय सच्ची राष्ट्रीय भावना के अनुरूप तथा काश्मीर सहित भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। काश्मीर के शेख अब्दुल्ला तथा अन्य लोग हमारे संविधान की रचना में भागी थे, जो प्रत्येक प्रकार से मुसलमानों की बहुसंख्या उसी संविधान को उसी प्रकार स्वीकार करने में हिचकिचाती है जिस प्रकार कि वह सारे स्वतन्त्र भारत पर लागू किया गया है। इस विषय पर कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। एक तर्क यह दिया जाता है कि हमारे संविधान में ही ऐसी व्यवस्था है कि सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा यातायात एवं परिवहन के अतिरिक्त संविधान में की धाराओं का लागू होना जम्मू तथा काश्मीर सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। लोग भूल जाते है कि इस विशेष धारा को प्रस्तावित करते हुए भी गोपाल स्वामी आयंगर ने स्वयं ही उस विशेष परिस्थिति का उल्लेख किया था जिसमें से यह राज्य उस समय गुजर रहा था और यह भी असंदिग्ध रूप से कह दिया था कि कानूनी धारा कुछ भी क्यों न हो इसमें कोई सन्देह नहीं किया कि यह राज्य अन्य राज्यों के समान विलय हो जायेगा और सावधानी से तैयार किये गये और प्रजातांत्रिक आधार पर खड़े भारतीय संविधान को स्वीकार करेगा। अतः जम्मू और काश्मीर के पक्ष में संविधान में दी गई किसी अल्पकालीन विशेष धारा के आधार पर भारतीय संविधान को स्वीकार न किए जाने के औचित्य को सिद्ध करना बच्चों की सी बात है। यह विचार बल पकड़ रहा है कि हमारे ही रक्त तथा धन से हम शेख अब्दुल्ला और उसके अनुयायियों के लिए एक लगभग स्वतन्त्र राज्य निर्माण कर रहे हैं। जम्मू तथा लद्दाख की जनता ने पूर्ण विलय के पक्ष में अपनी घोषणा

कर दी है। यदि काश्मीर घाटी के लोग भिन्न मत रखते हैं तो इस क्षेत्र के लिए अन्य कुछ विशेष उपबन्ध इस समय के लिए रह सकते हैं। हमें यह भी प्रायः बताया जाता है कि यदि भारतीय संविधान को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करने के लिए कोई अनुचित दबाव दिया गया तो काश्मीर घाटी के मुसलमानों की भारत से पृथक हो जाने की संभावना है। यह तर्क बिलकुल भी समझ में नहीं आता। यदि हमारा संविधान ऐसा बना होता जिससे मुसलमानों को अपने भविष्य के विषय में घबराहट होती अथवा उन्हें समानता का बर्ताव न मिलने की संभावना होती, तो शायद इस तर्क में कुछ जान दिखाई देती। किन्तु अब ऐसा नहीं है, फिर इस झिझक का कारण क्या हो सकता है? श्री जिन्ना की पाकिस्तान की विचारधारा का भी यही आधार था कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश कभी भी ऐसे संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे जो हिन्दू बहुसंख्या वाली संसद से समर्थित केन्द्रीय सरकार को व्यापक शक्ति देता हो। काश्मीर के संबंध में इस प्रकार के विचारों को प्रोत्साहन देना घोर सांप्रदायिक तथा प्रतिगामी कृत्य होगा। यह सब कुछ होते हुए भी, जैसाकि मैंने कहा, हम शेख अब्दुल्ला की राजधानी काश्मीर घाटी को किसी भी विशेष ढंग से जितने समय के लिए वे चाहें रखने को तैयार हैं, किंतु जम्मू और लद्दाख तो वहां की जनता की इच्छा के अनुसार पूर्णतः भारत में मिल जाने चाहिए। मैं इस बात को पुनः दुहराता हूं और स्पष्ट शब्दों में रखता हूं कि मैं जम्मू तथा काश्मीर का विभाजन नहीं चाहता। किंतु यदि शेख अब्दुल्ला अड़े हुए हैं तो जम्मू तथा लद्दाख का बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए। काश्मीर घाटी को भारतीय संघ के अन्तर्गत एक पृथक राज्य बनाया जा सकता है जिसे सब आवश्यक सहायता प्राप्त हो और वैधानिक रीति से उसके साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा शेख अब्दुल्ला और उनके सलाहकार चाहते हैं।

प्रजा परिषद् का आन्दोलन

प्रजा परिषद् के द्वारा आरम्भ किये गये आन्दोलन को अत्यधिक और जानबूझ कर गलत ढंग से रखा गया है। यह केवल दुर्भाग्य का विषय है कि जब जम्मू की जनता अपने आपको भारत के साथ जिसे वह अपनी पवित्र भूमि मानती है, एक रूप करना चाहती हो-जब भारत सरकार न केवल उसके स्वप्न की पूर्ति में बाधक ही हो वरन् उन्हें प्रतिगामी, देशद्रोही, यहां तक कि पाकिस्तान का मित्र कहकर पुकारे। क्या केवल धर्मनिरपेक्षता के विकृत विचार और शेख अब्दुल्ला और उसके मित्रों द्वारा प्रस्तुत मांगों के आगे समर्पण के कारण किसी की दृष्टि इससे भी और अधिक धुंधली हो सकती है? श्री नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों ने सम्मिलित रूप से जम्मू में भयंकर दमन की नीति अखत्यार की है। किन्तु मैं इस बात की असंदिग्ध रूप से घोषणा करता हूं कि दमन से यह समस्या हल नहीं होगी। जितना अधिक दमन होगा उतने ही घातक परिणाम होंगे। क्या श्री नेहरू और शेख अब्दुल्ला इस बात को नहीं जानते कि दमन से स्वयं उनके आन्दोलन नष्ट नहीं हुए थे? यही नहीं, इससे उन्हें भारी लाभ हुआ था। विलम्ब होने पर भी मैं श्री नेहरू और शेख अब्दुल्ला से निवेदन करूंगा कि वे दमन की इस नीति को छोड़ें और झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में न पड़ें। उन्हें जम्मू के वर्तमान नेताओं से बातचीत करनी चाहिए और एक ऐसे समझौते का मार्ग निकालना चाहिए जो सभी के लिए उचित तथा न्यायसंगत हो। इस दिशा में पहले कदम के रूप में जम्मू तथा काश्मीर की संविधान सभा यह स्वीकार करें कि राज्य अन्तिम तथा औपचारिक रूप से भारत के साथ मिल गया है। दूसरे, जम्मू काश्मीर विधान सभा यह स्वीकार करें कि नागरिकता, मूलभूत अधिकार, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र, वित्तीय एकीकरण एवं राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार सम्बन्धी भारतीय संविधान की धारायें उस राज्य पर भी लागू होती हैं। शेष के विषय में मेरा विश्वास है कि यदि पारस्परिक सद्भावना और समझदारी के बाद बातचीत चली तो एक सन्तोषजनक निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। जम्मू में आज की हालत चलने देना पूर्णतः अवांछित है और यह भी नेहरू तथा शेख अब्दुल्ला के हाथ में है कि वे जम्मू के जन-प्रतिनिधियों के सच्चे भय से दूर करें, जिससे सब मिलकर जम्मू-काश्मीर के एक तिहाई प्रदेश को मुक्त करने का उद्योग करें, जो भी हमारे राष्ट्रीय अपमान के रूप में पाकिस्तान के अधिकार में है। इस बीच में हमारी क्रियात्मक सहानुभूति जम्मू के उन सब लोगों के साथ है जो अधिकारियों के कोप की अग्नि को साहस से सह रहे हैं और एक श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए कष्ट उठा रहे हैं।

पूर्वी बंगाल

पूर्वी बंगाल की स्थिति से चारों ओर एक बेचैनी और क्षोभ उत्पन्न हुआ है और सारे देश ने एक स्वर से यह मांग की है कि भारत सरकार पूर्वी बंगाल में बचे हुए लगभग एक करोड़ हिन्दुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रति अनुरोध करें और प्रभावशाली कदम उठायें। विभाजन का आधार ही यह था कि भारत तथा पाकिस्तान दोनों ही में अल्पसंख्यक सुरक्षा तथा सम्मान के साथ रहते रहेंगे। भारत की सीमाओं में आज भी चार करोड़ से अधिक मुसलमान हैं। जहां तक अन्य अल्पसंख्यकों का प्रश्न है उन्हें कभी भी भय नहीं था और वे सदा की भांति शांतिपूर्वक यहां रह रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दू तथा सिख अल्पसंख्यक नाम शेष हो चुके हैं। पूर्वी बंगाल से भी लगभग 40-50 लाख हिन्दू अभी तक निकाले जा चुके हैं। हिंदुओं को बाहर निकालने की यह क्रिया समय-समय पर होती है जिसके परिणामस्वरूप भारी अपमान तथा कष्ट लोगों को उठाना पड़ रहा है। पारपत्र प्रणाली का आरम्भ ही एक निश्चित योजना तथा हिंदू विरोधी द्वेषभाव लेकर हुआ है। यह स्पष्ट ही है कि यदि पूर्वी बंगाल में शेष बचे 90 लाख हिन्दुओं को निकलकर भारत आना पड़ा तो हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायगी। इसके अतिरिक्त पुनः संस्थापन के लिए सरकार को जो भारी मात्रा में व्यय करना पड़ेगा वह अलग से। यदि अल्पसंख्यक वहां इसी तरह रहते रहे जैसे आज रह रहे हैं तो या तो उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा अथवा उनकी स्थिति एक दास की होगी। ■

क्रमशः

नहीं रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं 'कमल संदेश' के पूर्व संपादक प्रभात झा

(04 जून, 1957—25 जुलाई, 2024)

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं 'कमल संदेश' के पूर्व संपादक श्री प्रभात झा नहीं रहे। गुरुग्राम के एक अस्पताल में 25 जुलाई, 2024 को उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 67 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं।

अस्पताल में श्री प्रभात झा को अंतिम प्रणाम करने बड़ी संख्या में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। उनके पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश सोनी, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष, राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) श्री शिवप्रकाश, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, मध्यप्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा, म.प्र. सरकार के नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्री महेन्द्र कुमार, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री श्री ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी डॉ. संजय मयूख सहित अनेक नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

श्री प्रभात झा का पार्थिव शरीर 27 जुलाई को उनके पैतृक गांव कोरियाही (जिला-सीतामढ़ी, बिहार) लाया गया, जहां वे पंचतत्त्व में विलीन हो गए।

श्री प्रभात झा का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे श्रेष्ठ संपादक एवं कुशल संगठक थे। उनकी सहजता, सरलता, विनम्रता एवं उदारता के सभी कायल थे। उनकी जीवन-यात्रा में परिश्रम की पराकाष्ठा झलकती है। सामान्य परिवार में जन्मे श्री झा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई।

श्री प्रभात झा का जन्म 4 जून, 1957 को उनके ननिहाल हरिहरपुर (जिला-दरभंगा, बिहार) में हुआ था। उनके पिताजी का नाम स्व. पानेश्वर झा एवं माताजी का नाम स्व. अमरावती देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई (महाराष्ट्र) में हुई। इसके बाद 17 वर्ष की उम्र में वे ग्वालियर (मध्यप्रदेश) आ गए। यहीं पीजीवी कॉलेज से बी.एस.सी., माधव कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एम.ए. तथा एमएलबी कॉलेज से एल.एल.बी. की शिक्षा प्राप्त की।

श्री प्रभात झा ने पत्रकारिता एवं राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। वे 1986 से 1993 तक 'स्वदेश' समाचार-पत्र से पत्रकार के रूप में जुड़े रहे। बाद में वे इस पत्र के सहयोगी संपादक बने। इसके बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। 1993 से 2002 तक मध्यप्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी एवं बाद में प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात् 2003 से 2005 तक भाजपा प्रकाशन विभाग के राष्ट्रीय संयोजक रहे। 2005 से 2007 तक भाजपा संसदीय दल कार्यालय के अतिरिक्त सचिव का दायित्व संभाला। 2007 से 2010 तक भाजपा राष्ट्रीय मंत्री रहे, इस दौरान वे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार भी रहे। उन्होंने मई, 2010 से दिसंबर, 2012 तक मध्यप्रदेश भाजपाध्यक्ष एवं 2014 से 2020 तक भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने कई राज्यों में भाजपा प्रदेश प्रभारी के नाते कार्य किया। वे 2013 में आंध्र प्रदेश प्रभारी, 2014 में दिल्ली प्रदेश प्रभारी एवं 2015 में पंजाब प्रदेश प्रभारी बने। श्री प्रभात झा को मध्यप्रदेश से दो बार राज्यसभा सदस्य (2008-2014 एवं 2014-2020) बनने का सुयोग प्राप्त हुआ। वे राज्यसभा की याचिका समिति और आचार समिति के अध्यक्ष रहे। इसके साथ ही, वे कई समितियों के सदस्य रहे, जिनमें रेलवे, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण एवं आईटी समिति उल्लेखनीय हैं। श्री प्रभात झा अनेक संस्थाओं से संबद्ध रहे। वे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध फाउंडेशन के न्यासी एवं कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति न्यास के सचिव रहे।

श्री प्रभात झा ने भाजपा प्रकाशन विभाग को सशक्त करने में

शोक संदेश

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभात झा जी के निधन से अत्यंत दुःख हुआ है। मैंने उनकी कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है कि संगठन को सशक्त बनाने में उन्होंने किस प्रकार सक्रिय भूमिका निभाई। जनसेवा के अपने कार्यों के साथ ही उन्होंने पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। ओम शांति!

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्यप्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उनका संपूर्ण जीवन जनसेवा और संगठन को समर्पित रहा। उनका जाना भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करें और दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति!

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद श्री प्रभात झा जी के निधन से मुझे गहरी वेदना की अनुभूति हुई है। एक पत्रकार के रूप में शुरू हुआ उनका पूरा सार्वजनिक जीवन, जनहित और देशहित में समर्पित रहा। मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन को मज़बूती देने में भी उन्होंने बड़ी सराहनीय भूमिका निभाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति!

- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभात झा जी का निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। राष्ट्र व संगठन को निःस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले प्रभात झा जी ने मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में हमेशा जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाया। दुःख की इस घड़ी में पूरी भाजपा उनके परिजनों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति शांति शांति!

- अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रभात झा जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दें। मध्यप्रदेश के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका सदैव हमे प्रेरित करेगी। आपका निधन राजनैतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ॐ शांति!

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 2003 से 2006 तक पार्टी मुखपत्र 'भाजपा समाचार' उन्हीं की देखरेख में प्रकाशित हुआ। 2007 में डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास द्वारा नई पत्रिका 'कमल संदेश' हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया, बाद में इसके संपादक बने और जनवरी, 2024 तक इसके संपादक रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं के वैचारिक प्रबोधन की दृष्टि से समसामयिक विषयों पर सैकड़ों पुस्तिकाएं निकालीं। संसद में भाजपा सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों को पुस्तिका रूप में त्वरित प्रकाशित कराया। दर्जन भर 'कमल संदेश विशेषांक' निकाले, जो बहुप्रशंसित हुए। इन विशेषांकों में वे उच्चकोटि के विचारकों-लेखकों के लेख प्रकाशित करते थे।

श्री प्रभात झा के कुशल संपादन में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। अर्चना प्रकाशन से 2005 में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे पर केंद्रित 'शिल्पी' (तीन खंड) पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी प्रकाशन से 2008 में उनकी संपादकीय टिप्पणियों पर केंद्रित 'जन गण मन' (तीन खंड) पुस्तक प्रकाशित हुई। डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास से उनके संपादन में 2008 में 'अजातशत्रु पं. दीनदयाल उपाध्याय' पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रभात प्रकाशन से श्री प्रभात झा के संपादन में 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद', 'अंत्योदय', 'समर्थ भारत', 'गौरवशाली भारत', 'समाधान की ओर', 'हमारे अटलजी', 'विचारकों की दृष्टि में एकात्म मानववाद', 'Resurgent', 'Roadmap for A Glorious India' एवं 'कार्यकर्ताओं से' पुस्तकें प्रकाशित हुईं। वे जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून, स्वदेश, पंजाब केसरी सहित विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर आलेख लिखते रहते थे।

श्री झा ने 2009 में लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में आस्ट्रिया का प्रवास किया।

श्री प्रभात झा ने जहां पत्रकार एवं संपादक के नाते बौद्धिक रूप से राष्ट्रीय विचारधारा को पल्लवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, समसामयिक विषयों पर कई पुस्तकों का संपादन किया, 'कमल संदेश' से अनेक युवा पत्रकारों को जोड़ा और इसकी गुणवत्ता बढ़ाई, वहीं भाजपा में मीडिया एवं प्रकाशन विभाग की सक्रियता को गति प्रदान की तथा मध्यप्रदेश भाजपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अथक प्रवास कर पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान किया।

'कमल संदेश' परिवार भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं अपने पूर्व संपादक श्री प्रभात झा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ■

ताकि सबको मिले पूरा पोषक भोजन

जगत प्रकाश नड्डा

एनडीए शासन के दौरान दूसरी बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनने के बाद पिछले सप्ताह जब मैंने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यानी एफएसएसएआई का दौरा किया, तो मुझे वर्ष 2014 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने शुरुआती कार्यकाल का स्मरण हो आया। यह वह समय था, जब यह प्राधिकरण देश के खाद्य-सुरक्षा नियामक के रूप में खुद को स्थापित कर रहा था और उस पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए खाद्य मानक और नीतियां तय करने की बड़ी जिम्मेदारी थी।

22 अगस्त, 2016 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 के एक दशक पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मैंने पहली बार एफएसएसएआई टीम और विभिन्न हितधारकों से मुलाकात की, तो इस प्राधिकरण का दृष्टिकोण स्पष्ट था। इसका लक्ष्य नीतियों को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और नागरिकों व खाद्य व्यवसायों के बीच सामाजिक व व्यावहारिक परिवर्तन को बढ़ावा देना था। इन कोशिशों को 'ईट राइट इंडिया मूवमेंट' के तहत खूबसूरती से एकीकृत किया गया है, जिसने सभी भारतीयों के लिए 'सुरक्षित, स्वस्थ और सतत' भोजन सुनिश्चित करने का एक समग्र 'संपूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण' अपनाया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई हमारे देश के खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। एक मजबूत खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत खाद्य-नीतियों और मानकों की नींव पर ही गढ़ा जा सकता है। ऐसे में, यह जानकर खुशी हुई है कि एफएसएसएआई के वैज्ञानिक पैनल व विशेषज्ञ समितियों का काफी विस्तार हुआ है। इनमें 88 संगठनों के 286 विशेषज्ञ शामिल हैं। इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप मानदंडों और नीतियों के विकास की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है।

एफएसएसएआई की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेट के मानकों का सृजन है, जिनको साल 2023 में वैश्विक मिलेट (श्री अन्न) सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मानक कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के साथ साझा किए गए हैं। इससे मिलेट के वैश्विक मानकों के विकास और भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

> **जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो नागरिकों और उपभोक्ताओं को हमें साक्ष्य-आधारित जानकारी के माध्यम से विभिन्न खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर सशक्त भी बनाना होगा। तभी हमारा काम समग्रता से पूर्ण होगा। यहीं पर एफएसएसएआई का 'ईट राइट इंडिया' अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करके कि उपभोक्ताओं तक हर स्तर पर जरूरी जानकारी पहुंचे**

सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों व मानकों के विकास के साथ-साथ उनका प्रवर्तन और परीक्षण भी आवश्यक है। एफएसएसएआई के खाद्य-परीक्षण के बुनियादी ढांचे में बीते आठ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कैबिनेट ने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए 482 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। एफएसएसएआई ने 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' नाम से मोबाइल फूड लैब उपलब्ध कराकर दूरदराज के इलाकों में पहुंचना शुरू कर दिया है।

इन उपलब्धियों का उत्सव मनाते समय हमें वैश्विक स्तर पर उभर रहे रुझानों, जैसे कि वनस्पति आधारित प्रोटीन, प्रयोगशाला में विकसित मांस आदि को भी स्वीकार करना चाहिए। एफएसएसएआई ने नई श्रेणियों- जैसे वीगन खाद्य पदार्थों, जैविक उत्पादों व आयुर्वेदिक आहार के लिए सक्रिय रूप से मानक विकसित किए हैं और यह खाद्य-सुरक्षा के उभरते रुझानों के अनुरूप निरंतर अनुकूलन कर रहा है।

जैसे-जैसे वैश्विक खाद्य व्यापार का विस्तार हो रहा है, एफएसएसएआई कोडेक्स जैसे विभिन्न मंचों पर अंतरराष्ट्रीय नियामकों के साथ साझेदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना है। एफएसएसएआई ने साल 2023 में दिल्ली में पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन (जीएफआरएस) भी आयोजित किया, जो खाद्य नियामकों के लिए उभरती खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के बारे में मिलने और विचार-विमर्श करने के लिए अपनी तरह का पहला सहयोगी मंच है।

जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो नागरिकों और उपभोक्ताओं को हमें साक्ष्य-आधारित जानकारी के माध्यम से विभिन्न खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर सशक्त भी बनाना होगा। तभी हमारा काम समग्रता से पूर्ण होगा। यहीं पर एफएसएसएआई का 'ईट राइट इंडिया'

एफएसएसएआई, 2006 खाद्य-उत्पादों के लिए व्यापक मानकों को अनिवार्य बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे उपभोग के लिए सुरक्षित हैं

अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करके कि उपभोक्ताओं तक हर स्तर पर जरूरी जानकारी पहुंचे। इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है, ताकि हमारी पहुंच बढ़े और व्यावहारिक बदलाव को प्रोत्साहित किया जा सके। यह उपभोक्ताओं को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य विकल्पों की मांग करने के लिए सशक्त बनाता है और खाद्य व्यवसाय को बेहतर विकल्प प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है।

एफएसएसएआई, 2006 खाद्य-उत्पादों के लिए व्यापक मानकों को अनिवार्य बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे उपभोग के लिए सुरक्षित हैं। साथ ही, फूड लेबलिंग के नियम उपभोक्ता को एक सूचित विकल्प (इंफोर्मड च्वाइस) चुनने में सशक्त करते हैं। विज्ञापन और दावों की नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि खाद्य व्यवसायों द्वारा उत्पादों के बारे में कोई भ्रामक दावा नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने का पर्याप्त तंत्र प्रदान करके उनके सामने आने वाली आधुनिक चुनौतियों के समाधान में सहायक रहा है, विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों और असुरक्षित या घटिया भोजन से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में।

खाद्य सुरक्षा एक सामूहिक प्रयास है, और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह संपूर्ण सरकार (होल-ऑफ-गवर्नमेंट) और संपूर्ण प्रणाली (होल-ऑफ-सिस्टम) दृष्टिकोण को अपना रहा है। एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलों में उद्योगों और अन्य हितधारकों को शामिल करके एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पिछले दस वर्षों में भारत की खाद्य सुरक्षा स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदला है। इसके साथ ही, यह उभरती चुनौतियों का समाधान करने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। एफएसएसएआई का लक्ष्य अपनी प्रतिबद्धता और समग्र दृष्टिकोण से भारत को खाद्य-उत्पादन में ही नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और स्थिरता में भी वैश्विक गुरु बनाना है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं)

350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी का 'वाघ नख' भारत वापस आया

छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया ऐतिहासिक बाघ के पंजे के आकार का हथियार 'वाघ नख' 350 वर्षों के बाद 19 जुलाई, 2024 को भारत वापस लाया गया। मराठा शासक के सिंहासन पर बैठने की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 जुलाई को लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय से भारत लाए गए इस हथियार का पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा में भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडनवीस और श्री अजीत पवार, संस्कृति मामलों के मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार और सतारा के शाही परिवार के सदस्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने लंदन से हथियार लाने के लिए श्री मुनगंटीवार के प्रयासों की प्रशंसा की। ■

देश में रोजगार 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया

भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम केएलईएमएस (K: Capital, L: Labour, E: Energy, M: Materials and S: Services) आंकड़ों के अनुसार देश में रोजगार 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17.19 करोड़ है।

यह जानकारी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने 29 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 'भारत में रोजगार सृजन' नामक शीर्षक से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

मुंबई (महाराष्ट्र) में 13 जुलाई, 2024 को विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

लद्दाख में 26 जुलाई, 2024 को 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के दौरान स्ट्रैटेजिक 'शिंकुन ला सुरंग' परियोजना का पहला वर्चुअल विस्फोट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत मंडपम (नई दिल्ली) में 21 जुलाई, 2024 को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन अवसर पर 'रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स' प्रदर्शनी का अवलोकन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 27 जुलाई, 2024 को भाजपाशासित मुख्यमंत्रियों एवं उपमुख्यमंत्रियों से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 27 जुलाई, 2024 को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान एक समूह चित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 08 अगस्त, 2024
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह